GOVT. COLLEGE RAU, INDORE

ONE DAY NATIONAL WEBINAR

ON

CHALLENGES IN IMPLEMENTING

NATIONAL EDUCATION POLICY 2020

DATE - 22.08.2023

ABOUT WEBINAR :-

Govt. College Rau, Indore was founded in 2011 and since then it is persistently growing towards new horizon. The college is accredited 'B' Grade by NAAC and has recently got P.G. in 11 major subjects of Arts, Science & Commerce. The college adopts innovative methods of teaching and learning to improve the quality of higher education on a consistent basis. The college has a beautiful and lush green campus with students of different background studying in Arts, Science & Commerce, with affordable Education. Well experienced and renowned teachers strongly encourage students to nurture their future. It aims at providing quality education relevant with present scenario fostering innovation, leadership and entrepreneurial spirit to students. Our alumni have stood out in varied fields such as business & industry, administrative & regulatory services.

ABOUT COLLEGE :-

"Education is not preparation for life; education is life itself." –John Dewey Education is the foundation stone of life. It is important for developing a strong society which will lead to a strong nation. The National Education Policy 2020 is the first education policy of the 21st Century which aims to address the many growing developmental imperatives of our country. The Webinar focuses on discussing the issues and challenges faced during implementation of the National Education Policy-2020

Sub Themes :-

- *Integration of Vocational Education in Traditional Education.*
- *Road Map for Outcome Based Education.*
- *National Education Policy and Nature of Higher Education.*

CHIEF PATRON
DR. KIRANBALA SALUJA
ADDITIONAL DIRECTOR (INDORE DIV.)
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

शासकीय महाविद्यालय राऊ, इंदौर के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार ***"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन और उसकी चुनौतियां"*** *विषय से मैं आशा करती हूं कि यह वेबिनार मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बना कर विद्यार्थियों के लिए हितप्रधान बनाएगा। इस हेतु आयोजक संस्था के साथ सभी सहभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं।*

PATRON
DR. SUDHA SURESH SILAWAT
PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE RAU, INDORE

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में लागू करने वाला अग्रणी राज्य मध्यप्रदेश है इस नीति के माध्यम से मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के नवीन द्वार खुल रहे हैं। बदलते वैश्विक परिदृश्य में यह आवश्यक था कि हम विद्यार्थियों को रोजगार तथा व्यवहारिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। मध्यप्रदेश में इस योजना को लागू हुए 02 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे महाविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की चुनौती जैसे विषय का चयन किया है।

विभिन्न महाविद्यालयों से शामिल विद्वान प्राध्यापक इस बात पर मंथन करें कि इस नीति के क्रियान्वयन में कौन–कौन सी चुनौतियां आ रही हैं तथा उन चुनौतियों का समाधान हम कैसे करेंगे।

मुख्य वक्ता के रूप में विषय विशेषज्ञ डॉ. अजीत कुमार (Asst. Prof. School of Education IGNOU, New Delhi) तथा डॉ. केसरीलाल वर्मा (Vice Chancellor Chhatrapati Shivaji Maharaj University Navi Mumbai) नवीन शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जो विचार रखेंगे उनसे भी हम इसके क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बना सकेंगे।

मैं आशा करती हूं कि यह विचार मंथन आप सबके लिए लाभकारी रहेगा।

DR. DHIRENDRA SHUKLA
O S D
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION,
M.P. BHOPAL

राष्ट्रीय वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ. धीरेंद्र शुक्ल ओ.एस.डी उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल ने अपने वक्तव्य में बताया कि ***राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियां*** *एक ऐसा विषय है जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए बहुत ही प्रासंगिक है। जब उच्च शिक्षा विभाग के पास सेमिनार आयोजित करने के लिए वित्त विभाग से धनराशि प्राप्त हुई तब हम लोगों ने सोचा क्यों ना प्रदेश के समस्त 550 महाविद्यालयों को यह धनराशि आवंटित कर ऑनलाइन वेबिनार करवाया जाए ताकि कम धनराशि में अधिक कार्य हो सके। पहले इतनी ही धनराशि से केवल 50 से 60 महाविद्यालयों में ही सेमिनार आयोजित करवा पाए थे। ऑनलाइन वेबिनार करने का उद्देश्य यह भी है कि सभी कॉलेज से विभिन्न विषयों पर प्रदेश अधिकतम प्रोफेसर एवं शोधार्थी वक्ताओं के विचार, आलेख पत्र अथवा सारांश हमें पत्रिका अथवा पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो सकेंगे जिसे विभाग द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। महाविद्यालय को वेबिनार आयोजित करने के लिए शुभकामनाएं।*

CONVENOR
DR. ANIL SINGH
GOVT. COLLEGE RAU, INDORE

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि NEP 2020 को लागू करने में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। राज्य में सत्र 2021–22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू है। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में लागू किया है। इन दो शैक्षणिक सत्रों के दौरान हमने कई चुनौतियों का भी सामना किया है। इस वेबिनार के माध्यम से निश्चय ही हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने एवं सुचारू रूप से चलाने में होने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा कर उनके यथासंभव हल निकाल पाएंगे।

DR. AJITH KUMAR C.
ASSISTANT PROFESSOR
SCHOOL OF EDUCATION IGNOU
NEW DELHI

वेबिनार के प्रथम मुख्य वक्ता के रूप में IGNOU नई दिल्ली से डॉ. अजित कुमार उपस्थित थे। उन्होने नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में विस्तृत व्याख्यान दिया। शिक्षा नीति की पूर्ण संरचना एवं व्यावहारिकता पर केन्द्रित अपने व्याख्यान में उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नवीन बदलावों की ओर ध्यान आकर्षित किया। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होने बताया की Multi Disciplinary Education तथा Research University बनाई जाएगी। उच्च गुणवत्ता के सहयोग सेन्टर बनाएं जाएंगें। विश्वगुरू की तर्ज पर हर उच्च शिक्षा विभाग में अंर्तराष्ट्रीय छात्र ऑफिस बनाया जाएगा। फॉरेन यूनिर्वसिटी केम्पसेस को भारत में लाया जाएगा। विभाग द्वारा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम संचालित किये जाएंगे । स्नातक तथा स्नातकोत्तर प्रोग्राम की संपूर्ण संरचना के अंतर्गत प्रथम वर्ष सर्टिफिकेट, द्वितीय वर्ष डिप्लोमा तथा तृतीय वर्ष स्नातक डिग्री कहलाएगा। चतुर्थ वर्ष पूर्ण करने पर स्नातक डिग्री रिसर्च के साथ दी जाएगी। अपने वक्तव्य में उन्होंने पारंपरिक कक्षाएं तथा ऑनलाइन कक्षाओं के बीच अंतर समझाया। उन्होंने Learning Management System (LMS) के बारे में चर्चा की। शिक्षण जगत में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों जैसे शिक्षक की उपलब्धता, कोर्स फ्रेम करना, किसी भी मोड से अध्ययन करना, आदि शामिल करना। उन्होंने ऑनलाइन तथा डिजीटल ऐजुकेशन के बारे में समझाया। वर्चुअल लेब तथा डीजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा की। ऑनलाइन असेसमेंट तथा परीक्षा पद्धति समझाइ। अध्ययन के ब्लेंडेड मॉडल के बारे में बताया । अपने वक्तव्य के अंत में उन्होंने छात्रों की सुविधा के लिए बनाए गए "अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट" के बारे में चर्चा की। नई शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियों के संदर्भ में उन्होंने बताया की शिक्षकों को तथा छात्रों को मोटिवेट करने की आवश्यता है तथा डीजिटल साक्षरता की अनिवार्यता बताई।

Dr. Keshari Lal Verma
Vice Chancellor
Chhatrapati Shivaji Maharaj University
Navi Mumbai, Maharashtra

दिनांक 22.08.2023 को शासकीय महाविद्यालय राऊ में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार के द्वितीय मुख्य वक्ता डॉ. केसरी लाल वर्मा, ¼कुलपति, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय नवी मुंबई, महाराष्ट्र½ ने अपने वक्तव्य में बताया कि शिक्षा सीखने और सीखाने की क्रिया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाना है। आगे आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। वैश्विक स्तर पर ज्ञान के क्षेत्र में भारत को तैयार करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 धर्म, लिंग, जाति या पंथ के किसी भेदभाव के बिना सभी को बढ़ने और विकसित होने के लिए मंच प्रदान करती है और इसका उद्देश्य सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके मौजूदा जीवंत ज्ञान को बनाए रखना और उसकी देखभाल करना है।

नई शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक कक्षा तक की शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा को अपनाने और आगे की शिक्षा में मातृभाषा को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण तथा तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। वर्ष 2030 तक सभी को साक्षर बनाने का लक्ष्य रख गया है।

उन्होने बताया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को मौजूदा से बढाकर 50 प्रतिशत तक ले जाना है। देश में अनुसंधान कार्य को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जायेगी। विदेशी विश्वविद्यालय भी अपने परिसर भारत में खोलेंगे जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

डॉ. केसरी लाल वर्मा ने नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कई चुनौतियों की भी चर्चा की जिसमें उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, विश्वविद्यालयों में बुनियादी ढांचे में कमी तथा शिक्षकों की कमी को दूर करना प्रमुख हैं।

TABLE OF CONTENTS

S.No.	Title & Author	Page No.
1	NEP 2020: A Solution for Youth Unemployment in India - DR. ANIL SINGH	01-04
2	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की चुनौतियां - PROF. A.S. RAO	05-09
3	राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा का स्वरूप - DR. DEEPALI VERMA	10-13
4	Challenges, Problems, Obstacles and Suggestions for Improving the Quality of HEIs Regarding NEP 2020 - DR. K.R. KANUDE	14-19
5	Study of NEP 2020:Objectives , Features , Challenges and Suggestions - DR. MAHENDRA ALONE	20-25
6	रोज़गारपरक शिक्षा एवं बेहतर करियर प्रदान करने में नई शिक्षा नीति 2020 का योगदान – शासकीय महाविद्यालय राऊ के विशेष संदर्भ में - DR. M.S.DAWAR - MISS RUCHIKA KASHYAP	26-29
7	राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं उच्च शिक्षा का स्वरूप - PROF. MANISH MAHANT	30-34
8	Impact of New Education Policy (NEP-2020) on Students and their Holistic Development - DR. N.P. RAJPOOT	35-49
9	वर्तमान परिदृश्य में नई शिक्षा नीति की चुनौतियां एवं सुझाव (एक वर्णनात्मक अध्ययन) - PROF. REKHA VERMA	50-53
10	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऑनलाइन प्रवेश – समस्याएं एवं सुझाव - MISS JULEE RATHORE	54-56
11	विद्यार्थियों के समग्र विकास में पुस्तकालय की भूमिका– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में - MRS. MAMTA SOLANKI	57-58
12	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – अवसर एवं चुनौतियां - DR. D.C. RATHI	59-60
13	National Education Policy (2020) and its Implementation - DR. JYOTI TANEJA	61-64
14	National Education Policy 2020: Reformation in Education - PROF. HEMLATA THAKUR	65
15	नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – प्रभावशीलता - DR. MALTI SOLANKI	66
16	National Education Policy 2020 and Youth Empowerment - DR. SHWETA HARDIA	67
17	Libraries in view of National Educational Policy 2020 - DR. SUREKHA PANDIT	68

ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

NEP 2020: A SOLUTION FOR YOUTH UNEMPLOYMENT IN INDIA

Dr. Anil Singh

Professor
Government College Rau, Indore

Abstract

The best education system changes the destiny of the nation. All the developments in any country depend on the quality of education it provides to its citizens. A sustainable growth is only possible when there is a strong foundation of value system inculcated in its basic education system. The growth of nation is measured in terms of its economic development in which employment plays avery important role. Employment is a basic requirement for a happy livelihood and to improve the quality of life. It also plays a major role in social and economic development of any nation. On the contrary, unemployment increases poverty, stress, crime rate and imbalance in social and economic status. Unemployment leads the youth to social evils like dishonesty, immorality, drinking, gambling, robbery etc. India has one of the youngest populations in the world. India enjoys a demographic dividend where more than 50 percent of its population is youth. The best education policy is necessary to handle these issues of unemployment. The paper attempts to study the importance of National Education policy 2020 and problem of unemployment among the youth of India.

Research methodology:

This research is a descriptive study. The necessary secondary data was collected from various websites including those of Government of India, magazines, journals, other publications, etc. This data was then analyzed and reviewed to arrive at the inferences and conclusions.

Key Words: NEP 2020, unemployment, policy, higher education, holistic.

Introduction:

Education system is the foundation to all the developments in a country. It is a guiding principle to suggest where the nation should go. It moulds the minds of the youth and make them participate in national development. Youth is the valuable human resource of every country. The young Indiashould be guided and should be utilized for the progress of the nation. Unemployment leads the youth to social evils like dishonesty, immorality, drinking, gambling, robbery etc. India has one of the youngest populations in the world. India enjoys a demographic dividend where more than 50 percent of its population is in the working age group of 15 to 59 and 28 percent in age group 15-29.According to Confederation of Indian Industry (CII) report it is said, "If India does not create enough jobs and its workers are not adequately prepared for those jobs, its demographic dividend may turn into a liability. And education and skill development will be the biggest enablers for reaping this dividend." Hence, the present National Education Policy 2020 aimed at finding solutions for the socio-economic problems of India. NEP 2020 is a document that focusses on practical and holisticeducation based on our Ancient Indian Knowledge System mixing with modernity.

What is NEP?

National Education Policy (NEP) is a set of policies formulated by the Government of India to promote education amongst Indian people. NEP is basically a comprehensive framework to guide the development of education in the country. India has seen three education policies in its post-

independence history. Education Policy lays particular emphasis on the development of the creative potential of each individual. It is based on the principle that education must develop not only cognitive capacities - both the 'foundational capacities 'of literacy and numeracy and 'higher-order'cognitive capacities, such as critical thinking and problem solving – but also social, ethical, emotional capacities and dispositions. The new education policy must be provided to all students, irrespective of their place of residence, a quality education system, with particular focus on historically marginalized, and under represented groups. Education is a great leveler and is the best tool for achieving economic and social mobility, inclusion, and equality. Initiatives must be in place to ensure that all students from such groups, despite inherent obstacles, are provided various targeted opportunities to enter and excel in the educational system.

Unemployment and the New Education Policy: Over the past few years, employability has remained a top challenge for employers as well as job seekers.

The National Education Policy of 2020 was announced by the Ministry of Human Resource and Development which aimed to bring about a change in the Indian education system to meet the employment needs of the 21st century and to wipe off unemployment. This new policy sought to rectify the poor literacy rate in primary schools, reduction in school dropout rates and adopt a multi-disciplinary approach in the higher education system. In addition, the NEP 2020 also focuses on restructuring the curriculum and pedagogy by focusing on childhood care, restructuring exams and assessments and investing in teacher training programs. In other words, the National Education Policy also aims at bringing about a holistic change in the education system, and the effectiveness of the system will depend upon the reduction of unemployment

NEP 2020: Solution to Employment Rate in India:

For a long time now the Indian education system was being questioned for its lack of effectiveness. Business leaders struggled to find job-ready talent and job-seekers grappled to find a job where their skills match the demand but now the future looks promising with a new revised policy in process that aims to focus on the holistic development of the emerging workforce- students. This new policy has proposed significant changes in school and higher education. The National Education Policy, 2020 is meant to provide an over arching vision and comprehensive framework for both school and higher education.If implemented effectively, the policy can help reshape the future of the workforce and help the emerging job seekers become more job-ready. With the new policy coming in picture, the school and college education will not only be seen as a facilitator of degree but it will be treated as a medium to build personality and it will help the students in their holistic professional growth. the new policy seems to focus more on skill development over points like just building a good "report card" and hence, will lead to the creation of a more educated and employable Indian population. Choice Based Credit System & a break from traditional career path". NEP empowers the future workforce with more flexibility to choose their courses.There will be no hard separation among 'curricular','extracurricular ', or 'co-curricular', among 'arts', 'humanities', and 'sciences', or between 'vocational' or 'academic' streams." to close the gap in achievement of learning outcomes, classroom transactions will shift, towards competency-based learning and education. A focus on essential subjects, skills, and capacities relevant for all.The traditional education system lacked the focus on building such competencies but the new policy has increased the scope of learning beyond subject-matters and made learning these skills essential.

India needs to create employment opportunities for the hundreds and thousands of young men and women who graduate from our colleges and universities every year. According to International labor Organization (Global employment trends for youth 2022) Like many countries in the world, India experienced severe working-hour and employment losses in 2020, and once again during

another, shorter, period in 2021. However, in contrast to most other countries, Indian youth employment in 2021 deteriorated with respect to 2020, despite an overall average improvement in the labor market. Meanwhile in the field of higher education, many changes are witnessed in the country. According to AISHE Report, Gross enrolment ratio in higher education recorded at 27.1 percent in 2019-20, slightly higher from 26.3 percent in 2018-19. For males, it has also increased from 26.3 percent in 2018-19 to 26.9 percent in 2019-20 while for females it has increased from 26.4 percent to 27.3 percent respectively. Youngsters in the age group 15 to 24 years hold the greatest promise as the source for economic growth of a nation. This is the age when people graduate from educational institutions and step into the labour markets to chart a career or at least make a livelihood. People usually complete high school (12th standard) by 18 years of age, graduation by 21years and postgraduation by 23 or 24 years. The transition from education to employment begins at different stages for different people during these years. In India, most people seem to make this transition after high school. Education may never end, but in the modern world, employment must begin somewhere between 15 and 24 years of age. The new education policy builds confidence among the youth as the skills are taught at the early level. Project works, interrnships and innovative research permitted in UG education helps build the career.The NEP tackles several important gaps inthe present education system - it creates a more holistic approach, dedicates a much higher investment, focuses on gross enrollment; it is, ideal in every manner. One of the major practical problems that arise from the same is unemployment. The National Education Policy has many significances. First it has realised the importance of educating the child in the formative years i.e.from 3 to 8 as it is believed that these years are vital for shaping the child's future. Secondly, it has broken from the stringent division of science, arts and commerce, thereby laying the foundation of the multidisciplinary approach. Thirdly, it acted as the meeting point for skills and education. This acted as a paradigm shift in education. Fourthly, the New Education Policy made education more inclusive by leveraging online pedagogy and learning methodologies for escalating mass enrolment in higher education. Fifthly, the NEP 2020 states that universities among the top universities in the world will be able to set up campuses in India. This will make way for the placements to take place and thus more educated people will be given employment. Most importantly, the NEP 2020 emphasises imparting education in the mother tongue till Grade 5 as it is considered the best way of teaching.

Suggestion:

NEP 2020 is a comprehensive document with holistic objective to transform the face of the country from India to Bharat. The policy will be successful when all the stakeholders participate in implementing it. It has to absorb the best element and mix ancient Indian knowledge system for a better future of the entire world.

Conclusions:

To conclude it can be said that the New Education Policy aimed at making the education system more holistic so that once passing from high school, students do not face difficulty in finding jobs. Since the inception of this education policy, the unemployment rate over the last two years has been reduced.The unemployment problem in India can be solved with the best implementation of NEP 2020. The youth will be benefitted by the policy as it is more student friendly. The purpose of NEP 2020 is to give what the students need and not the institution offers.This would lead to interest-based education and need based learning. It is hoped that the complete implementation of policy would lead to great outcomes. Indian youth would be empowered with best vocational skills in future.

Works Cited

1. International labor Organization Report

2. AISHE Report

3. NEP 2020 Regulations

4. Global Employment Trends for Youth 2022

5.NEP 2020 Draft Document

ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की चुनौतियां

अनुराग सिंह राव
सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र,
शासकीय महाविद्यालय राऊ, इन्दौर

भूमिका :– प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्युशस का कथन है कि **"अज्ञानता एक ऐसी रात्री के समान है जिसमें न चांद है और न तारे"** इसीलिए किसी राष्ट्र की **"दशा और दिशा"** का निर्धारण करने के लिए शिक्षा सर्वोपरि है। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता के पश्चात देश के नीति निर्माताओं ने यह महसूस किया कि भारत के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि तो हुई पर उच्च शिक्षा का स्तर वैश्विक परिदृश्य के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ था। इसलिए 1948–49 में महान शिक्षाविद् सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राधाकृष्णन आयोग का गठन कर विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार, उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ के साथ व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक नैतिक, शारीरिक तथा प्रबंधकीय, उद्योग, व्यवसाय और वाणिज्य की शिक्षा पर बल दिया गया।

इसी तारतम्य में **1953 में भारत सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना** की गई। साथ ही शिक्षा के उत्थान के लिए समय–समय पर निम्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया।

01 माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति	1952–53
02 माध्यमिक शिक्षा आयोग	1952–53
03 भारतीय शिक्षा आयोग	1964–66
04 राष्ट्रीय शिक्षा नीति	1986
05 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति	1992
06 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	1995
07 सर्व शिक्षा अभियान	1999
08 शिक्षा का अधिकार अधिनियम	2009
09 राष्ट्रीय शिक्षा नीति	2020

इस प्रकार विश्व के सभी राष्ट्रों की शिक्षा का उद्देश है अपने राष्ट्रों की संस्कृति, सामाजिक मूल्यों, राष्ट्र में उपलब्ध संसाधनों के द्वारा एक विद्यार्थी में निम्न गुणों का समावेश करना उन्हें राष्ट्र का सच्चा, कर्तव्यनिष्ट और उत्तरदात्यिवपूर्ण नागरिक का निर्माण करना।

शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य :–

- मानव के बौद्धिक विकास में वृद्धि
- व्यक्तित्व का निर्माण
- मानव में सभ्यता के गुणों का समावेश
- नैतिक उन्नति का प्रयास
- आर्थिक विकास में योगदान
- सामाजिक अनुकूलन में सहायता प्रदान करना
- जीवन को पूर्णता प्रदान करना

इस प्रकार देश की युवाशक्ति को राष्ट्र का सच्चा, कर्तव्यनिष्ठ और उत्तरदायित्व पूर्ण नागरिक बनाने में शिक्षा का सबसे अधिक और महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिखा है कि **''शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है।''**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

वैश्विक स्तर पर तीव्रगति से सर्वांगीण क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों को दृष्टिगत रखकर वर्तमान समय के नीति निर्माताओं ने **''वैश्विक शिक्षा विकास संकल्पना के अनुरुप भारत में सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा''** व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों में वृद्धि किए जाने के लक्ष्य से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉ. के. कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2022 से देश में लागू किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्यः–

- शिक्षा कों उत्कृष्ट बनाकर, भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना।
- भारत की संमृद्ध ज्ञान परंपरा से शिक्षा को जोड़ना।
- मातृभाषा के महत्व में वृद्धि करना।
- विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकियों से परिपूर्ण कर वैश्विक विकास के स्तर से तालमेल स्थापित करना।

- शिक्षा के साथ ही साथ विद्यार्थियों में कौशल संवर्धन में वृद्धि कर व्यक्ति की रोजगार मूलकता में वद्वि करना।
- विद्यार्थियों के अंदर समस्या–समाधान, तार्किक एवं रचनात्मक रूप से चिंतन करने के गुणों को विकसित करना।

इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें **"देश के विकास संबंधित अनिवार्य आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर राष्ट्र के विद्यार्थियों को ग्लोबल सिटीजन बनाना है।"** सौभाग्य से मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य है, जिसने 28 अगस्त 2021 को प्रदेश के राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के उच्चशिक्षा मंत्री माननीय डॉ. मोहन यादव जी के आतिथिय में इस शिक्षा का शिक्षा नीति का विधिवत उद्घाटन कर राज्य के युवाओं को वर्तमान परिस्थितियों के साथ तालमेंल कर शिक्षित होने का सुअवरसर प्रदान किया है।

: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ :

इस प्रकार मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का तृतीय वर्ष है। परंतु मध्य प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति, पाठ्यक्रम के निर्माण, नीति एवं नियमों की उपलब्धता, प्रदेश की सामाजिक परिस्थितियों आदि के कारण उक्त शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में निम्न चुनौतियों का सामना शिक्षा जगत के लोगों एवं विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है:–

- **शैक्षणिक संस्थानों में आधारभुत संसाधनों की न्यूनता :–** मध्यप्रदेश के शैक्षणिक संस्था विशेषकर ग्रामीण अंचल के शासकीय महाविद्यालय में आधुनिक तकनीकियों से शिक्षा प्रदान करने हेतु आधारभुत संसाधनों की अत्यंत कमी है। जैसे कम्प्यूटर सुविधा, नेटवर्क सुविधा, स्मार्ट बोर्ड, ई–लाइब्रेरी सुविधा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम अनुरूप पुस्तकों की उपलब्धता आदि।
- **असंतुलित शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात :–** प्रदेश के अधिकांश शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों के अनुपात में संबंधित विषयों में विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात में अत्यधिक अंतर होने के कारण शैक्षणिक गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा है।
- **कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम के अनुरुप संसाधन एवं स्टॉफ की कमी :–** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरुप विद्यार्थियों को रोजगार मूलक शिक्षा प्रदान करने हेतु 25 विषयों के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम व्यवहारिक रूप में विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। परंतु सैद्धांतिक रूप में इस पाठ्यक्रमों को सीखने और सीखाने के लिए संस्थानों में प्रयोगशालों एवं दक्ष शिक्षकों का अभाव इस नीति को प्रभावशाली नहीं बनाने दे रहा है।

- **ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धिः–** विगत 2021–22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में (स्नातक स्तर) के विद्यार्थियों में ड्रॉप आउट का प्रतिशत 15-20 % या उससे भी अधिक देखने को मिल रहा है। जिस पर चिंतन की आवश्यकता है।
- **व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की कमी :–** राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतगर्त विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यावसायिक एवं व्यवाहारिक ज्ञान प्रदान करने हेतु प्रशिक्षुता/शिक्षुता, परियोजना कार्य एवं सामुदायिक कार्य/सेवा कार्य पाठ्यक्रमों का भी प्रावधान है। परन्तु उक्त व्यावसायिक एवं व्यावहारिक पाठ्यक्रमों को सीखने–सीखाने के लिये प्रशिक्षण संस्थानों की अनुपलब्धता है जहाँ विद्यार्थियों को उक्त कौशल में दक्ष किया जा सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव

- शैक्षणिक संस्थानों में **आधुनिकतम प्रणाली से शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक संसाधनों** जैसे **कम्प्युटर, नैटवर्क सुविधा, स्मार्ट बोर्ड, ई–लाईब्रेरी एवं नई शिक्षा नीति के अनुरूप आवश्यक पुस्तकों की उपलब्धता** शीघ्रता से पूर्ण की जानी चाहिए।
- **शिक्षक विद्यार्थी के अनुपात के असंतुलित अंतर को दुर करने** के लिये उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन कों त्वरित रूप से कार्यवाहि करनी चाहिए।
- **कौशल संर्वधन के पाठ्यक्रम के अनुरूप महाविद्यालयों में प्रयोगशाला हेतु बजट, संसाधनों एवं दक्ष स्टॉफ की पुर्ती** हेतु शासन को पहल करनी चाहिए।
- ड्रॉपआउट विद्यार्थियों की संख्या में कमी लाने के लिये **स्कूल स्तर से ही विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अध्ययन हेतु नीवं तैयार** करनी चाहिए।
- प्रशिक्षुता/शिक्षुता जैसे व्यावसयिक कौशल संर्वधन के पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिये **नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध स्वरोजागर के केंद्रों** जैसे RSETI आदि के साथ शासन स्तर पर अनुबंध कर, इन संस्थानों को महाविद्यालयिन विद्यार्थियों को कौशल विकास संबधित प्रशिक्षण देने के लिये निर्देशित किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिये **उपलब्ध नियमों में पाइजाने वाली कमियों** के लिये प्रदेश स्तर के प्राध्यापकों से चर्चा कर, **कमियों का युक्ति युक्त तरिके से समाधान** किया जाना चाहिए।

: संदर्भ ग्रंथ सूची :

- अग्रवाल भरत एवं मुकर्जी रविन्द्रनाथ – समाजशास्त्र

- नन टी.पर्सी – एजुकेशन : इट्स डाटा एडं फर्स्ट प्रिंसिपल
- श्रीवास्तव ए. पी एवं गजपाल एल.एल – समाजशास्त्र
- शंकर राव सी.एन. – सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी
- उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.शासन – नई शिक्षा नई उड़ान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा का स्वरूप

डॉ. दीपाली वर्मा
सहायक प्राध्यापक,
शास.महाविद्यालय राऊ, इन्दौर

सारांशः

शिक्षा, पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने एक न्याय संगत और न्याय पूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा से आर्थिक और सामाजिक प्रगति होती है इसलिए प्रत्येक देश अपनी परंपरा के अनुसार अलग–अलग शिक्षा प्रणाली अपनाते हैं क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए स्कूल और कॉलेज स्तर पर एक अच्छी तरह से सोची समझी और परिभाषित की गयी भविष्य की शिक्षा नीति की आवश्यकता होती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, यह भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

NEP 2020, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर किया गया एक सुधार है जिसके लिए जनवरी 2015 में, पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक समिति गठित की गयी जिसने नई शिक्षा नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया को शुरु किया इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जून 2017 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक पैनल द्वारा 2019 में एनईपी का मसौदा प्रस्तुत किया गया था नीति का उद्देश्य यह है की 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए प्रयास किया जाये तथा किसी को भी किसी भाषा विशेष का अध्ययन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। एनईपी में भाषा नीति की प्रकृति में व्यापक दिशा निर्देश दिए गए।

प्रस्तावना–

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने तथा एक न्याय संगत व न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत् प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। सार्वजनिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा।

शिक्षा से आर्थिक सामाजिक प्रगति होती है, इसलिये प्रत्येक देश अपनी परंपरा के अनुसार अलग अलग शिक्षा प्रणाली अपनाते है क्योकि किसी भी देश के विकास के लिए स्कूल और कॉलेज स्तर पर एक अच्छी तरह से सोची समझी और परिभाषित की गई भविष्य की शिक्षा नीति की आवश्यकता होती है।

राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, यह भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर नई शिक्षा नीति 2020 एक सुधार है। यह नीति व्यापक है इसमें प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो रूपरेखा बनाई गई है उसमें उच्च शिक्षा के साथ–साथ भारत के ग्रामीण और शहरी दोनो क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी स्थान दिया गया है।

ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सन् 2030–2032 तक भारत दस ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित जी.डी.पी. के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बडी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तो यहां ये बात ध्यान देने योग्य है कि दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्थाएं भारत के प्राकृतिक संसाधनों से संचालित नही की जा सकती इनको संचालित करने के लिए ज्ञान के संसाधनों की आवश्यकता पडेगी और इस आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए, भारतीय शिक्षा क्षेत्र के विकास को बढावा देने के लिए वर्तमान सरकार ने राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरू करने का निर्णय लिया है।

अध्ययन के उद्देश्य–

01. नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानना।
02. नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों एवं सिद्धांतों के बारे मे जानना।
03. नई शिक्षा नीति 2020 पुरानी शिक्षा नीति से किस प्रकार भिन्न है, इसको जानना।
04. नई शिक्षा नीति में अभिभावकों एवं शिक्षकों हेतु क्या नवाचार है? को जानना।

शोध प्रविधि–

यह लेखपत्र द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से लिखा गया है। इस हेतु विभिन्न रिपार्ट, समाचार पत्रों एवं पुस्तकों से तथ्यों का संकलन किया गया है।

साहित्य की समीक्षा–

संक्षेप में, इसमें पिछले अध्ययनों की समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो इस अध्ययन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है। इसमें नई शिक्षा नीति 2020 और विशेष रूप से उच्च शिक्षा से संबंधित अध्ययनों पर किए गए कार्यों की एक झलक देखने को मिलती है।

सिंह दुर्गेश 2020 ने अपने लेख पत्र में लिखा है कि भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था त्रीस्तरीय है जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा भाामिल है। यह शिक्षा व्यवस्था शिक्षित लेकिन रोजगार विहिन युवाओं को तैयार करती है। जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तर के कुशल एवं दक्ष युवा तैयार करने में सक्षम नहीं है। सरकार को इसके लिए शिक्षा में निवेश करना होगा। यद्यपि सरकार ऐसा कर भी रही है। देश में 34 सालों बाद नई शिक्षा नीति आई है जो भोधपरक, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देती है। सरकार का यह प्रयास है कि 45 हजार से अधिक महाविद्यालयों और 15 लाख से अधिक स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप परिवर्तन किया जाए तथा तेजी से बदलते सामाजिक आर्थिक वैश्विक परिवेश में देश के युवाओं को सक्षम बनाया जाए।

कुरियन अजय और चंद्रमना सुदीप के शब्दों में, "नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा पूरी तरह से कई लोगों द्वारा अप्रत्याशित थी। नई शिक्षा नीति 2020 ने जिन बदलावों की सिफारिश की है, वे कुछ ऐसे थे जिन्हें कई शिक्षाविदों ने कभी आते नहीं देखा। यद्यपि शिक्षा नीति ने स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को समान रूप से प्रभावित किया है, यह लेख मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति 2020 और उच्च शिक्षा पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है। यह पत्र नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताओं को भी रेखांकित करता है और विश्लेषण करता है कि वे मौजूदा शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं। नई शिक्षा नीति में रीयल–टाइम मूल्यांकन प्रणाली और परामर्शी निगरानी और समीक्षा ढांचे के लिए आश्वस्त रूप से प्रावधान किया गया है। यह शिक्षा प्रणाली को पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हर दशक में एक नई शिक्षा नीति की अपेक्षा करने के बजाय, अपने आप में लगातार सुधार करने के लिए सशक्त बनाएगा। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय

उपलब्धि होगी। नई शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा के लिए एक निर्णायक क्षण है। प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन ही इसे वास्तव में पथप्रदर्शक बना देगा।

नई नीति का विजन ही ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जिसमें भारतीय परम्पराओं और मूल्यों को जगह मिले। शिक्षा प्रणाली में इण्डिया की जगह भारत की झलक मिले। इसका उद्देश्य ऐसी समतावादी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली बनाना है जिससे एक ज्ञान आधारित समाज का निर्माण हो। इसमें प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक ज्ञान को शामिल किया गया है। इस नीति के प्रमुख सिद्वान्त इस प्रकार है–

1. हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना।
2. बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना।
3. शिक्षा में लचीलापन लाना ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के अनुसार पाठ्यक्रम चुनने की आजादी हों।
4. कला एवं विज्ञान, पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर गतिविधियों में, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में विरोध एवं अलगाव की भावना नहीं हो।
5. एक बहु विषयक और समग्र शिक्षा का विकास करना।
6. अवधारणात्मक सोच का विकास करना न कि रटंत एवं परीक्षा की पढ़ाई पर जोर।
7. रचनात्मक एवं तार्किक सोच का विकास करना ताकि नवाचारों को प्रोत्साहन मिले।
8. नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का विकास करना।
9. बहुभाषा शिक्षा प्रणाली अपनाना ताकि अध्ययन–अध्यापन कार्य में भाषा की शक्ति को पहचान मिल सके।
10. जीवन कौशल अर्थात आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना।
11. सीखनें के लिए सतत् मूल्यांकन पर जोर देना न कि परीक्षा को महत्व देना ताकि कोचिंग संस्कृति का बिना हो सकें।
12. शिक्षा को सरल एवं सुलभ बनाने के लिए तकनीक पर जोर देना।
13. विविधता और स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना।
14. सभी शैक्षणिक निर्णयों में पूर्ण क्षमता और समावेशन को ध्यान में रखना।
15. विद्यालय से महाविद्यालय शिक्षा तक सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों में तालमेल एवं सामंजस्य बिठाना।
16. शिक्षकों एवं संकाय को सीखने का केंद्र मानते हुए इनकी भर्ती आदि हेतु उन्नत सुविधाओं का विकास करना।
17. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर के शोध का विकास करना।
18. भारतीय परम्पराओं एवं गौरव का विकास करना। देश की प्राचीन एवं आधुनिक संस्कृति, ज्ञान एवं परम्पराओं का समावेश करना।
19. शिक्षा को सार्वजनिक सेवा मानते हुए इसे प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाए। इस हेतु आवश्यक प्रयास करना।
20. मजबूत और जीवंत शिक्षा प्रणाली हेतु शिक्षा में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी एवं सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।

सभी पाठ्यक्रमों में सुधार प्रारम्भ से ही किया जाएगा। शिक्षा के व्यावसायिकरण पर रोक लगेगी। अगर कोई संस्थान अतिरिक्त कमाई करता है तो उसे शिक्षा के विकास में खर्च करना होगा। शिक्षा का क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पर किया गया विनियोग कभी भी बेकार नहीं जाता। शिक्षा में बार–बार नवीन परिवर्तन करने की बजाए मौजूदा योजनाओं को ही सही व्यवस्था एवं तरीकों से लागू करना चाहिए। गरीब और वंचित वर्गों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। एक कल्याणकारी देश की उन्नति एवं उन्नत भविष्य के लिए युवाओं को ऐसी शिक्षा देने की नीति होनी चाहिए कि वे भावी

परिर्वतनों में अपने आप को समायोजित करके अपना विकास कर सके। नई शिक्षा नीति 2020 का इस प्रकार से क्रियान्वयन करना है कि सभी को विकास के उचित अवसर मिल सके।

संदर्भ

1. सिंह दुर्गेश, क्रॉनिकल मासिक पत्रिका, मई 2020, पृष्ठसंख्या 80–81
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
3. https://en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Policy_2020
4. https://pmmodiyojana.in/national-education-polic/
5. https://pmmodiyojanaye.in/national-education-policy-2020/

ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

CHALLENGES, PROBLEMS, OBSTACLES AND SUGGESTION FOR IMPROVING THE QUALITY OF HEI IN NEP 2020

Dr. K.R. Kanude
Govt. College Rau, Indore

The National Educational Policy 2020 focuses on Affordability, Accessibility, Quality, Equity, and Accountability to ensure lifelong learning. India is a fast-growing country with over 1113 universities and over 42000 HEIs. To boost the Indian education system the current Government introduced NEP 2020 which has a vision for transforming our country into a society of equal and living knowledge, by providing quality education for all. NEP emphasizes Multidisciplinary education, digital literacy, improving communication skills, problem-solving, logical reasoning, and Vocational education and skilling through a comprehensive framework. However, they are many challenges our country needsto face to implement it. This paper discusses the challenges HEIs would be facing to promote continual learning and create opportunities for all stakeholders to meet Sustainable Development Goals 2030.
Keywords: National Educational Policy 2020, Affordability, Accessibility, Quality, Equity, andAccountability.

Introduction:

A Survey on NEP was conducted, and 50 instructors from Telangana's rural and urban institutions responded to the survey. Ten questions were provided in a Google form, and the approach of a selective sample survey was utilized to learn about the issues and how people understood NEP. The difficulties in practice that they might encounter if NEP is adopted were gathered. Finally, solutions to the problem areb sugeested.

If successfully implemented while considering the real-world difficulties facing our current educational system, pedagogy will become more experimental, holistic, integrated, learner-centered, discovery-oriented, adaptable, and entertaining. Prime Minister Modi did describe in his speech how NEP 2020 seeks to develop Indian students into global citizens and hopes to properly guide them into the 21st century.

Results:

As educators, we are all looking forward to accepting these much-needed changes to our educational system with an open mind and optimism. We have great faith that the adoption of this eagerly awaited regulation will open up a whole new universe of knowledge for our future generations. NEP 2020 will undoubtedly have a significant impact on the production of high-quality human resources who will be prepared to face challenges in the path of future success by providing them with the necessary skills, values, and attitudes to lead our country in the desired direction of economic growth and development.
Keywords Equity, Vocational Education, Universalization of education, Holistic.

1. Do you think a budget of 6%of GDP for education is enough to reorient our education system assuggested by NEP 2020?

Yes = 38.5
No= 61.5

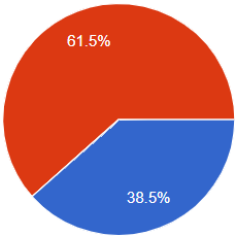

2. Do you think there will be privatization of education if NEP

is implementedYes = 63.5
No = 38.5

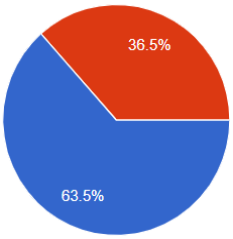

3. Do you think vocational education must be started at the school level?

Yes = 21.2
No= 78.8

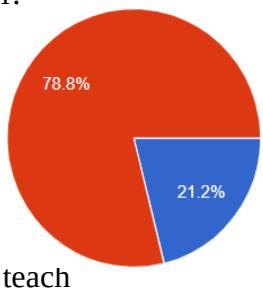

4. Are the Teachers with present knowledge if trained will be able to teach multidisciplinary kindof education?

Yes = 86.5
No= 13.5

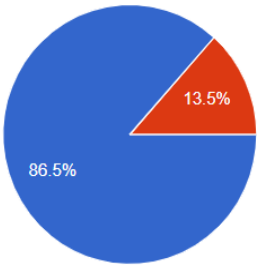

5. With a multiple-entry system do you think students would come back for higher educationYes = 82.

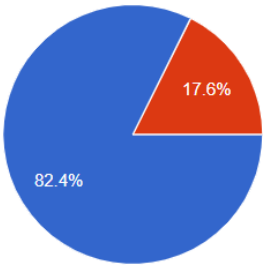

What do you think are challenges for the implementation of NEP 2020

Most of them believed that the largest problem was increasing funds while also providing faculty training for people. It is more difficult to cultivate a research mindset through projects, internships, and the creation of research cells without trained teachers. The development of infrastructure, scientific thinking, and technology in society to reach out to

remote locations is the other difficulty. The unwillingness to depart from rote learning. Few people anticipated an increase in the dropout rate in higher education because of frequent exits and entrances.

Discussion on Challenges

This mega-education policy's nationwide implementation will be a monumental job involving several stakeholders at different levels, including the state, district, and Mandal levels. A significant challenge for educational leadership and governance will be fostering cooperation and a sense of shared ownership among important stakeholders, including the private sector, at the state and district levels where there is diversity. The NEP Drafting Committee, headed by K. Kasturirangan, correctly noted that India's educational system is underfunded, highly bureaucratized, and lacks the the capacity for innovation and scale-up

The private sector is crucial for implementing the NEP's objectives, especially when dealing with the higher education system. It should be emphasized that the private sector manages up to 70% of higher education institutions (colleges and universities). Aside from this, as the majority of students enroll, the private sector contributes much-needed financial resources and innovation. To extract the contribution of the private sector and acknowledge it as an equal partner in the NEP process, the government and regulatory organizations must establish practical institutional procedures.

The central government must establish a balance between the public and private sectors. The foundational tenets of NEP, Quality, and Equality will be impacted by the complete privatization of higher education. In this regard, the NEP has declared that the government must increase public spending on education to 6 percent of GDP to achieve the aims of the new policy. If one considers the previous promises and their actual fulfillment, this is a difficult assignment. For example, the 1968 National Education policy suggested allocating 6% of the GDP to education. Although public spending on education has increased throughout the years, it has never exceeded 3%. How such enormous quantities of money can be spent on education doesn't yet have a clear road map. GDP would have to be set aside for investments in infrastructure and training.

The Right to Education Act of 2009 and the New Education Policy of 2020's applicability has raised legal issues that have added to the criticism of the policy. The planned Higher Education Commission of India (Repeal of University Grants Commission Act) Act, 2018, which was still pending, as well as the Foreign Educational Institutions (Regulation of Entrance and Operations) Bill, 2010, are yet to make their impact on the education ecosystem. If the budget is adequate, we will need to open one new University every week for the next 15 years to double the Gross Enrolment Ratio in higher education by 2035, one of the policy's declared objectives. The National Education Policy 2020's emphasis on multidisciplinary learning in higher education is a very welcome move, but it calls for a shift in perspective because departmentalization is pervasive. The British left a legacy in our contemporary educational system; NEP is currently copying Principles from the Americans. Parents, teachers, grandparents, and educators from two or more generations must be involved in the mental transformation to implement it properly. The

NEP must take over from a generation that prioritized Science education over Arts and Humanity, rethinking and implementing instructional adjustments are the need of the hour.

Recommendations of

We need 'multidisciplinary education' and not multidisciplinary Universities. Converting all higher educational institutes to degree-granting entities, may not solve the problem. Let the system evolve at its own pace. Let the free market decide the course of evolution. Instead of directing the independent educational entities in which direction to grow and defining the process of growth, create an environment, an ecosystem conducive to the growth taking stakeholder opinions and market needs.

- As a step towards multidisciplinary education, facilitating collaborations between already existing degree-granting institutes in the domains of humanities, social and pure sciences, engineering, management, law, and medicine may be a more feasible idea. Focus on capacity building for high- quality research:
- Give importance to vocational education along with encouragement to the student to continue furtherstudies. An entrepreneurial spirit is to be encouraged through new start-ups and promoting incubation centers. Vocational Education with internships.
- Skill development is happening but till now the impact is not visible. We need to put more focus. Skills about job demands must be taught.
- The curriculum, activities, and industry linkages need to be redesigned keeping in mind the demandfor skill sets and knowledge.
- Institutes of eminence with world-class quality must be established. Release the existing resourcesfor the expertise that is needed.
- Some policy matters need to be presented before Parliament for further changes.
- Higher Education Commission of India Bill to be passed at an early date.
- The Board of Governors for universities requires amendments to the Central and State UniversitiesActs.
- NRF an autonomous trust must come out as an Act at an early date.
- Mother tongue as the medium of instruction till 5th class must depend on student decision rather onState Government or Center.
- Funds must be given to Affiliated colleges to grow into Autonomous institutions.
- There must be an elected body for Regulatory institutions with democratic governance.
- Greater emphasis is to be laid on leadership and governance.
- Enormous funding to establish large HEIs will lead to Privatization and steps must be taken to strikea balance between public and private institutions.
- The undue importance of language and religion must be avoided.
- Central Government must participate in the dissemination, advocacy, and evolution process of NEP and implement it with proper understanding, clarification, and consensus with nodal agencies.
- Government must prepare the teachers, administrators, and leaders to know the nuances.
- Institutions must plan strategies for Institutional Development, Faculty Development, andTechnology induction.

- Institutions must Partner with NGOs, Industries, Corporate to share resources and guarantee learningoutcomes.
- Perform with well-defined goals, concrete measures, available resources, and regular evaluation.
- Propose changes to the policies taking feedback at all levels.
- The Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE)-2009 needs to be reviewed immediately.
- Many financing sources must be made available in order to support research centers, the publication of papers, the creation of an ecosystem to support entrepreneurship, and incubation centers.
- Indian knowledge systems, including tribal and indigenous knowledge, must be accurately and methodically included in the curriculum to promote Indian Ethos. Language Universities must be established and promoted.
- National Research Foundation is another great idea. However, if these spaces get filled by individuals who are driven by ideological agendas, little could be expected. So care must be taken in this regard.
- Projects, and internships must be made mandatory at the undergraduate level.
- Technological penetration to the remote areas to remove digital undivided.
- Taking steps to prevent dropout rates in higher education.
- Addressing issues of policy implementation and diversity issues in an unbiased way.
- The growth of higher education in India has to be largely guided by the serviceable needs of thedriving economy.
- The change can occur only through a systemic approach to change as also the development of its human resource and networking the system through information and communication technology.
- Gender disparity and ethnic differences must be removed.
- Every human activity will need the expertise of experts as we transition to a learning society, which will bring the entire field of higher education into stark relief.
- Industry and students alike anticipate the availability of specialized courses to ensure that they receive the most up-to-date and effective education and are prepared for employment. To enable students to enroll in specialized programs, vocational and diploma courses need to be made more appealing. To make teaching and research more appealing to the younger generation, incentives should be given to these professions.

Conclusion

In conclusion, the NEP 2020 is an incredibly ground-breaking and innovative document. The Policy itself has an impressive view, but the real difficulty is in actually putting it into practice. Given that education is on the concurrent list of the Constitution, several states are sure to object. The policy seeks to meet the needs of India in the twenty-first century among other things by addressing pedagogical problems, structural disparities, and expanding access. The NEP's most difficult challenge is simultaneously fixing several

flaws in the educational system. The NEP 2020 drafting committee has made a thorough effort to create a policy that considers many points of view, international best practices in education, practical experience, and stakeholder feedback. Although the aim is idealistic, the implementation plan will determine whether it actually promotes an inclusive education that equips students, academia, and industry for the future. Through education conventional activities including research, innovation, teaching, human resource development, and continuing education, universities in India have been a major conduit for the advancement and transmission of knowledge and International cooperation is another function that is becoming more crucial. By implementing NEP let's make India the "knowledge hub" of the world that it was by achieving the goals as soon as we can.

References

1. Kalyani Pawan. (2020). An Empirical Study challenges that have global dimensions, higher being one of them. This is due to the greater development of transportation and communication on NEP 2020 [National Education Policy] with Special Reference to the Future of the Indian Education System and Its Effects on the Stakeholders. Journal of Management Engineering and Information Technology-JMEIT,7(5),17.
2. http://doi.org/10.5281/zenodo.4159546
3. National Education Policy 2020.
4. https://en.wikipedia.org/wiki/National_Policy_on_Education
5. Khaitan, S. (2020, August 7). NEP 2020: Why Learning in Mother Tongue Is Effective but Hard toImplement. Business Standard.
6. www.business-standard.com/article/education/nep-2020-why-learning-in-mother-tongue-iseffective- but-hard-to-implement-120081200399_1.html.
7. Raman, S. (2020, November 20). Vocational Education in the NEP 2020: Opportunities andChallenges. SPRF.
8. B.A., P. V. (2020, July 31). 'Vocational courses may distract poor students.' The Hindu. https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/vocational-courses-may-distract- poorstudents/article32244096.ece
9. Desk, I. T. W. (2020, August 14). A reality check on NEP 2020: 6 major challenges inimplementation. India Today.
10. NEP 2020: Challenges, Criticisms, Way Forward. (2020, August 7). Indian Policy Collective.
11. Khaitan, S. (2021, January 26). Budget Explainer: How India Funds Public School Education. Indiaspend.
12. Digital Literacy in India: Structural Constraints and the NEP 2020 – SPRF. (2020, September 4).SPRF.
13. Chari, R. (2020b, August 30). NEP 2020: Empowering the teacher. Times of India.

ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

STUDY OF NEP 2020: OBJECTIVES, FEATURES, CHALLENGES AND SUGGESTIONS

Dr. Mahendra Alone
Assistant Professor; Dept. of Zoology
Govt. P.G. College Rau

Abstract

A well-defined education policy and the future is important for the country at school and college levels because of the fact that education leads to economic and social development. Different countries use different education systems with due regard to culture and traditions and take different stages during their life cycle at school and college education levels to make it work. The National Education Policy 2020 (NEP 2020), approved by the Indian Union Cabinet on July 29, 2020, sets out the vision for India's new education system. The new policy replaces the previous National Education Policy, 1986. This policy is a comprehensive framework for primary education towards higher education and vocational training in rural and urban areas of India. This policy aims to transform India's education system by 2021. Shortly after the policy was released, the government made it clear that no one would be forced to learn any particular language and that the method of teaching would not be diverted from English to any regional language. The language policy in the NEP is a school to decide on the application.Education in India is a study of the Related List.Policy 2020. A national education policy should be applied to all schools in India by 2022.

Keywords: Higher Education, National Education Policy 2020, NEP-2020, Overview and Analysis, Implementation Strategies, Methods, Challenges, Opportunities for NEP 2020

Research Methodology

This is a conceptual paper. So the study collected the information from secondary sources i,e websites, articles in newspapers , popular magazines , scholarly journals , etc.

Introduction

National Education Policy 2020 for Higher Education The National Education Policy 2020 i.e. NEP 2020 is a comprehensive education policy introduced by the Government of India in

July 2020. NEP 2020 aims to transform the education system in India by providing access to education for all, promoting diversity, equity, and inclusion, and preparing students for the 21st century.

NEP 2020 has introduced 5+3+3+4 education structure where the first five years of education are foundational, promoting multilingualism, emphasizing vocational education and skills training, introducing common entrance exams for university admissions, and leveraging technology to enhance learning outcomes.

Objective of NEP

The National Education Policy 2020 for higher education aims to transform the existing higher education system in India. This policy emphasizes on promoting interdisciplinary studies, introducing new subjects, and providing flexibility in courses and fresh opportunities for students. It aims to increase the Gross Enrolment Ratio (GER) in higher education, provide multiple entry and exit options, and allow students to choose courses according to their interests and aptitude.

The policy envisions setting up of a National Research Foundation, a National Education Technology Forum, and setting up of more Higher Education Institutions in the country. The policy is aimed at creating a holistic and flexible education system that is adaptive to the needs of the 21st century.

National Education Policy 2020 for Higher Education Features

The policy aims to increase the Gross Enrolment Ratio (GER) in higher education to 50% by 2035.

Around 5 crore seats to be added in higher education. The policy proposes the establishment of a National Research Foundation (NRF) to fund and promote research in all disciplines. The policy recommends the establishment of a single regulator for higher education, called the Higher Education Commission of India (HECI), to replace multiple regulatory bodies. The policy proposes the introduction of a four-year multidisciplinary undergraduate degree,

with multiple exit options and opportunities for skill development. The policy proposes the establishment of a National Educational Technology Forum (NETF) to promote the use of technology in higher education. The policy recommends the development of a credit-based system for degree programs, which would enable students to pursue multiple degrees or programs simultaneously. The policy proposes the establishment of a National Academic Credit Bank (NAC-Bank) to facilitate the transfer and accumulation of academic credits across institutions.

Challenges of National Education Policy 2020 for higher education. **Overhauling of higher education system**: The National Education Policy 2020 proposes a major overhaul of India's higher education system. While this could potentially create a more streamlined and effective system, some stakeholders are concerned about the challenges that could arise during the transition.

Financing: The policy proposes several new initiatives such as setting up of new universities, restructuring of the education system, and promoting online education. Implementing these will require significant funding, and the government needs to find ways to finance them without putting an additional burden on the taxpayers.

Bridging the Digital Divide: The policy envisions promoting online education and making it accessible to all, including those living in remote areas. However, this will require bridging the digital divide, which remains a challenge in a country where many people still lack access to basic internet connectivity.

Faculty Development: The policy places a strong emphasis on faculty development and training, but there is a shortage of qualified faculty in many areas of higher education, and it may take time for institutions to build the necessary capacity.

Equity: While the National Education Policy 2020 seeks to promote equity and inclusion in higher education, there are concerns that some of the proposed measures, such as the four-year undergraduate program, may disadvantage students from marginalized communities or those with disabilities.

Cooperation - Education of states is a concurrent subject. This is why most states have their school boards. Therefore, the State Governments have to come forward for the actual

implementation of this decision. Also the idea of bringing a National Higher Education Regulatory campus as the top controlling organizationcan be opposed by the states. **Expensive Education** - The new education policy paves the way for admission to foreign universities. Various academics believe that admission to foreign universities is likely to be expensive for Indian educational system. As a result, it can be challenging for lower class students to pursue higher education.

Sanskritisation of education - South Indian states charge that the government is trying to Sanskritise education with the tri-language formula. Many problems can arise in front of states even if the medium of education for children is in mother tongue or regional language. For example, people from different states live in a union territory like Delhi. In such a school there will be children who know different mother tongues. In which medium all these children will be educated, Whether or not English medium schools are in agreement with the vernacular concept. In primary school, in which medium the children will be able to get an education if the state changes.

Feeding-related inadequate investigation - Fees still exist in some states Regulation exists but these regulatory processes are unable to curb profiteering as unlimited donations. **Financing** - Ensuring funding will depend on how strong the will power to spend the proposed 6 percent of GDP as public expenditure on education.

Lack of human resources - Currently skilled teachers in elementary education lacks. In such a situation, the implementation of the system made for elementary education under the National Education Policy 2020.

SUGGESTIONS FOR NEW EDUCATION 2020 POLICY OF INDIA

The initial 5 years are included in early childhood care education. It will be implemented through Anganwadi. First, Anganwadi should be converted into Kids Zone so that the child can get an education in sports. Also, one of the two Anganwadi workers should be replaced by an ASHA worker and physiotherapy so that both education and health will work together. It is said that 85% of brain development takes place in this period. Therefore, to prepare a strong and capable generation in this, skilled training will have to be made available to the children in this period. Will receive education from class 3 to class 5 in the primary stage. Children between 8 and 11 years of age come. In this class, the child has to reduce the burden

of books. In this phase, children should get an education through moral stories so that the round development of the child is possible. Bagless education should be imparted at this stage. In the secondary stage, the child develops knowledge about his environment. The government not only distributes bicycles, mid-day meals to children, as well as the facility of de-warding like Navodaya. Because of the economic problem in rural areas of India, they are unable to get an education by engaging in agricultural work and leave their education in between. Also, 50% evaluation textbook and 50% evaluation should be based on local arts promotion, culture and small cottage industries only then the concept of employment education will come true. In the presence of parents in addition to the provision of custom education in the higher secondary stage abstain from sexual education also. Internships in various areas of the country to the child through vocational training and entrepreneurship should be given so that children are aware of the geographical environment. Implementing all the declarations requires the strong political will of basic infrastructure.

Less money is spent on research in India The National Research Foundation will be set up as an apex body to conduct research and to promote strong research culture and research potential in higher education. In the new education policy, emphasis will be laid on the establishment of education centers for the gender inclusion fund and deprived areas. The student's report card will be evaluated based on a 360-degree assessment, keeping in mind the mental abilities of his behavior, which will be evaluated by the student's classmate and teacher.

The implementation of the NEP 2020 will require coordinated efforts from all stakeholders, and it remains to be seen how effectively the policy will be implemented. However, the NEP 2020 is a step in the right direction towards transforming India's education system to meet the demands of the changing world.

Conclusion

Overall, the paper concludes that while the NEP 2020 offers a comprehensive vision for education reform in India, its implementation is fraught with challenges and limitations. The success of NEP 2020 will depend on the governments ability to address these challenges and ensure the participation of all stakeholders in the process of education reform.The policy

recognizes the importance of multidisciplinary education, research, vocational education, teacher education, and the use of technology in higher education. The policy aims to make India a hub for research and development, attract talent from around the world, and prepare students for the changing job market.

REFERENCES

1. Amar Ujala 31 July 2020; now studying till 5th, an examination for admission in mother tongue till graduation.
2. Dainik Jagran 30 July 2020; Let us know why a new national education policy was needed to change the education system of the country. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_EN_Revised.pdf
3. Draft National Education Policy 2019. Committee for Draft National Education Policy, Ministry of Human Resource Development, Government of India. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_EN_Revised.pdf
4. Govt. of India (1968). National Policy on Education,1968 https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE-1968.pdf
5. Govt. of India (1986). National Policy on Education, 1986
6. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE86-mod92.pdf
7. Govt. of India (2020).National Education Policy 2020. https://www
8. Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Education Ministry of Human Resource Development. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/ files/NEP_Final_English_0.pdf education board exam, major changes in graduation degree, learn special things,
9. Hindustan Times 2020.08.08; 'NEP will play role in reducing gap between research and education in INDIA.

ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

रोज़गारपरक शिक्षा एवं बेहतर करियर प्रदान करने में नई शिक्षा नीति 2020 का योगदान – शासकीय महाविद्यालय राऊ के विशेष संदर्भ में

डॉ. एम. एस. डावर
(सह प्राध्यापक, वाणिज्य)
सुश्री रूचिका कश्यप
(कम्प्यूटर ऑपरेटर)
शासकीय महाविद्यालय राऊ, इन्दौर

नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार करना है। इस नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक रूप से महाशक्ति बनाने का प्रयास किया जाएगा।इसके अलावा भारत में शिक्षा का सावभौमीकरण भी किया जाएगा। जिससे कि शिक्षा प्रत्येक छात्र तक प्रदान की जा सके। इस नीति को सभी शिक्षण संस्थानों में वर्ष 2030 तक लागू कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति जानने के साथ–साथ हमें उसके उद्देश्य जानने चाहिए। नई शिक्षा नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना।
2. एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाना।
3. बच्चों को अनुशासन सिखाना और सशक्तिकरण करना।
4. एजुकेशन पॉलिसी को पारदर्शी बनाना।
5. इवैलुएशन पर जोर देना।
6. ओपन एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना।
7. बच्चों की सोच को क्रिएटिव करना।
8. गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन डेवलप करना।
9. रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देना।
10. एक साथ कई लैंग्वेज पर फोकस रखना।

भारत सरकार ने हाल ही में देश की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। इस नई शिक्षा नीति से छात्रों की उच्च शिक्षा व वैश्विक एक्सपोजर के नए मार्ग प्रशस्त होंगे, भविष्य में देश में एक आधुनिक और बेहतर शिक्षा व्यवस्था देखने को मिलेगी । देश में उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान की संख्या बढ़ेगी, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का भारत में कैम्पस निर्माण इस शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ऑनलाइन शिक्षा ने पहले ही छात्रों के आगे बढ़ने के कई मार्ग खोल दिए हैं। इससे एक नवीन शिक्षा प्रणाली से देश में बेहतर एकेडेमिक व्यवस्था के साथ साथ रोज़गार के अवसर भी तैयार होंगे।

नई शिक्षा नीति के साथ कदम मिलाते शासकीय महाविद्यालय राऊ

नई शिक्षा नीति के साथ कदम मिलाते हुए मध्य भारत का शासकीय महाविद्यालय राऊ भी आगे बढ़ रहा है। शासकीय महाविद्यालय राऊ, मध्य प्रदेश (इंदौर) में स्थित है। महाविद्यालय रोजगारपरक शिक्षण व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है , छात्रों को शिक्षा, संस्कार व भविष्य की चुनौतियां व संभावित अवसर के अनुसार तैयार किया जाता है। 34 वर्ष बाद आई यह नवीन शिक्षा नीति देश में शिक्षा के भविष्य को बदलने में सक्षम है। उच्च शिक्षा में होने वाले बदलाव जैसे ग्रेजुएशन में कई एक्जिट प्वाइंट का होना, उच्च शिक्षा 3 या 4 वर्ष का होना आदि देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। छात्रों को एक या दो वर्ष का पीजी प्रोग्राम व 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड बैचलर व मास्टर प्रोग्राम भी प्रदान किया जाएगा। शिक्षा एक निवेश है, हर कोई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसे भविष्य के अवसरों के अनुरूप अच्छी योग्यता और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। शासकीय महाविद्यालय राऊ में पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों के मूल्यों को बरकरार रखते हुए आधुनिक शिक्षण विधियों और सुविधाओं को अपनाया गया है।

उच्च शिक्षा क्षेत्र में नए आयाम गढ़ता शासकीय महाविद्यालय राऊ

शासकीय महाविद्यालय राऊ आज मध्य भारत में उच्च शिक्षा में एक प्रतिष्ठित नाम है शहर के कई प्रख्यात शिक्षाविद, मोटिवेशनल स्पीकर, करियर कंसल्टेंट्स संस्थान से जुड़े हुए है। निम्नलिखत बिंदु शासकीय महाविद्यालय राऊ को एक बेहतरीन महाविद्यालय बनाते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्ररिप्रेश्य में म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तीयों का योगदान

सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। जिसके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित करती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिससे कि वह शिक्षा की प्राप्ति कर सकें।

छात्रवृत्ति एक प्रकार की आर्थिक सहायता को कहते हैं, जिसे विद्यार्थियों को आगे की शिक्षा में आर्थिक रूप से सहायता एवं मानसिक रूप से प्रोत्साहन हेतु प्रदान की जाती है। इसे प्रदान करने का आधार मुख्य रूप से मेधावी अथवा निर्धन विद्यार्थियों से होता है। इसके जरिये मेधावी छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वे अपनी पढ़ाई किसी बड़े विद्यालय में कर सकते हैं, एवं ऐसे छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हैं, उन्हें भी इस सहायता के कारण पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं आती है।

यह एक प्रकार की सहायता होती है, इस कारण जहां शिक्षा हेतु लिए गए ऋण को लौटाना होता है, वहीं इसे लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आगे की अच्छी पढ़ाई ही इसके उद्देश्य को पूर्ण कर देती है। इसे प्रदान करने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि इससे वे विद्यार्थी अपने क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के साथ ही आगे चल कर कुछ अच्छा कार्य करेंगे।

छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता की जरूरत है। आज उच्च शिक्षा पहले से कहीं अधिक महंगी है जिससे छात्रों को अपने पसंद के पाठ्यक्रम और कॉलेजों को वहन करना कठिन हो रहा है। प्रतिभाशाली भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा का खर्च वहन करने में वित्तीय चुनौतियों और कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसलिए भारत सरकार उन्हें छात्रवृत्ति देकर वित्तीय मदद प्रदान करती है । पहले विभिन्न शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया लंबी कागजी कार्रवाई के कारण छात्रों के लिए एक मुश्किल काम था। सरकार द्वारा शैक्षिक छात्रवृत्तियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह दौड़ना पड़ता था।

Mptaas छात्रवृत्ति पोर्टल एक अद्वितीय और सरल मंच है जो छात्रों के लिए एक कुशल और पारदर्शी तरीके से शैक्षिक छात्रवृत्ति का लाभ उठानें में मदद करने के लिए बनाई गई है एवं वे छात्र जो पोस्ट मेट्रीक छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए पात्रता नहीं रखते परंतु ऐसे छात्र/ छात्राये जो बहुत अधिक मेहनती है वे उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते है एवं धन के अभाव के कारण वे अपना सपना पूरा नही कर पाते है। उनकी इसी समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार ने **मेधावी विद्यार्थी योजना** को आरम्भ किया है। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार राज्य के मेधावी विधार्थी को स्नातक स्तर तक पूर्ण प्रवेश शुल्क और पाठ्यक्रम शुल्क प्रदान करती है। साथ म.प्र. सरकार ने **मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना** भी बनाई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित कामगारो के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से वह सभी छात्र जिनके माता–पिता मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कामगार के रूप में पंजीकृत हैं उनकी उच्च शिक्षा का शिक्षण शुल्क मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब प्रदेश के छात्र आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनको उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी। इसके अलावा यह योजना प्रदेश के नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने में भी कारगर साबित होगी।

छात्राओं को विषेश रूप से प्रोत्साहन करने हेतु सरकार द्वारा निम्न योजनाएं चलाई गई है –

गांव की बेटी योजना – ग्रामीण क्षेत्रो की प्रतिभावान बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं उच्च शिक्षा की और प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप मे प्रतिवर्ष 5000रु की राशि गांव की बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। इस योजना की जानकारी महाविद्यालय की वेबसाईड पर उपलब्ध है। इस योजना मे राशि प्रोत्साहन राशि के रूप दी जाती है, इसलिए बालिकाएँ मेधावी योजना, कर्मकार योजना, पोस्ट– मेट्रिक छात्रवृत्ति के साथ भी इस योजना का लाभ ले सकती है। प्रथम वर्ष की परीक्षा पास होने पर ही द्वितीय वर्ष मे इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसी प्रकार द्वितीय वर्ष की परीक्षा पास करने पर तृतीय वर्ष मे इस योजना का लाभ दिया जाता है।

प्रतिभा किरण योजना – गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली शहर की मेधावी छात्राओं के शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप मे प्रतिवर्ष 5000 रु की राशि प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं उच्च शिक्षा का स्वरूप

मनीष महन्त

सहायक प्राध्यापक

(राजनीति शास्त्र)

शासकीय महाविद्यालय राऊ इन्दौर

शिक्षा मानव जीवन के सर्वागीण विकास का सर्वोत्तम साधन है । प्राचीन काल मे भारतवर्ष में शिक्षा व्यवस्था मानव को उच्च आदर्शो को प्राप्त करने हेतु अग्रसर करती थी। वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के समग्र विकास कालखण्ड मे सहयोग प्रदान करती थी।

कालखंड में व्यवस्था मे परिवर्तन आया वर्तमान में डॉ. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता मे तैयार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को अस्तित्व मे आई। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह शिक्षा नीति महज एक सर्कुलर नही अपितु महायज्ञ है, जो देश कीनींव रखेगा।

शिक्षा नीति में यह बदलाव 34 वर्ष के अंतराल के बाद किया गया है, बदलाव अपेक्षित था, एवं समयानुकूल था। पूर्व की शिक्षा व्यवस्था' जहाँ मात्र सीखने और परिणाम केंद्रित थी, वही नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक बहुविषयक, अन्तः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की उपयोगिता पर केंद्रित है, जिसका ध्येय विद्यार्थी का सर्वागीण विकास करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में म.प्र. शासन का उच्च शिक्षा विभाग अग्रणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत में शिक्षा को उत्कृष्ट बनाना और भारत को वै ि वक स्तर पर ज्ञान के क्षेत्र मे महाशक्ति बनाना, भारत की प्राचीन समृद्ध ज्ञान परम्परा से शिक्षा को संयुक्त करना, मातृभाशा को महत्व प्रदान करना, विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, शिक्षा के साथ–साथ विद्यार्थियों का कौशल संवर्धन करना है ।

जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य विद्यार्थियों को वै ि वक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाना है, वहीं म.प्र. शासन ने भारत सरकार की भावना को मूर्तरुप, प्रदान करते हुए म.प्र. के समस्त राज्य/ निजी विश्वविद्यालयो मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.को लागू कर दिया है।

मनुष्य जीवन में प्रतिभा एवं दक्षता ईश्वर प्रदत्त तथा प्रयास से प्राप्त करने योग्य भी होती है, किंतु उसका संपूर्ण विकास अवसर एवं परिस्थितियों पर भी निर्भर होता है परिस्थितियों का प्रभाव न केवल व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व विकास पर अपितु व्यक्ति के माध्यम से संपूर्ण समाज पर प्रभाव डालता है। अन्ततःयह व्यक्तित्व संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मानव में अन्तर्निहित प्रतिभा, क्षमता, दक्षता को उद्घाटित करने की दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अत्यंत आवश्यकताहै । किसी भी राष्ट्र की वैश्विक पहचान उसकी संस्कृति, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति,

एकता, वैज्ञानिक प्रगति, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की दशा पर और साथ आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर करती है। आने वाले दशक मे भारत जब विश्व की सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला देश होगा तो हमारा उत्तरदायित्व वैश्विक स्तर पर और बढ़ जायेगा। युवाओं का उज्ज्वल भविष्य युवाओं को उच्च स्तर की ' गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने से ही संभव हो पाएगा।

विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के दौर मे वैश्विक शिक्षा विकास संकल्पना के अनुरूप भारत में युवाओं के लिए ऐसी शिक्षा की संकल्पनाकी गयी जो समावेशी एवं सर्वउपयोगी, सर्वसुलभ और सबसे अधिक रोजगार उन्मूलक हो।

अतीत पर दृष्टि डाले तो यद्यपिभारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा समृद्धशाली रही है लेकिन समय सापेक्ष नूतन प्रयोग अपेक्षित थे। अतः जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में प्राचीन ज्ञान परम्परा, संस्कृति, धरोहर को सहेजने व समृद्ध करने पर बल दिया गया है वही वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में जो तेजी से बदलाव आया है उसके अनुरूप वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान से विद्यार्थियों मे वैज्ञानिक सोच पैदा हो। आज जब Global villageकी अवधारणा विश्व में रोजगारमूलकता के साथ, सीखने की कला के साथ विद्यार्थी समाधानमूलक चिंतन विकसित कर सके, रचनात्मक मौलिक चिंतन को बढ़ावा मिले इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर विविध विषयों, यथा कला, वाणिज्य व विज्ञान के मध्य अन्तर्सम्बन्धों के बारे मे विद्यार्थियों को मुक्त रूप से चिंतन–मनन करने का अवसर मिलने का प्रबंध किया गया।

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ध्येय रहा कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिनमें तकनीकी, व्यावसायिक समझ, वैज्ञानिक अध्ययन साथ मानविकी विषयों की समझ विकसित की जाए। एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक भावनाप्रधान साहित्य का भी सृजन कर सके और एक वाणिज्य का अध्येता साहित्य पर मनन कर सके। वास्तव में प्राचीन गुरुकुल परम्परा में सर्वांगीण एवं अर्न्तविषयक अध्ययन पर ही बल दिया जाता था जो विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास पर बल देता था लेकिन समयानुसार शिक्षा खण्डों में एवं रोजगारमूलक नहीं रह पायी। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में विज्ञान के विषयों के साथ विद्यार्थी कला एवं वाणिज्य के विषयों को भी अपने अध्ययन की विषयवस्तु बना सकता है। एक कला का विद्यार्थी करारोपण व गणित का भी अध्ययन कर सकता है वहीं विज्ञान एवं वाणिज्य का विद्यार्थी भारतीय संविधान, मानव अधिकार एवं सामाजिक समस्याओं का समग्रता से अध्ययन कर सकता हैं।

व्यक्तित्व' विकास अब खण्डों में नहीं वरन समग्रता में पुष्पित–पल्लवित हो सकेगा। विद्यार्थी रोजगार की

दृष्टि से तो तैयार होंगे ही साथ ही नैतिकता, तार्किकता एवं संवेदनशील भी होंगे।

परम्परागत शिक्षा प्रणाली में 'जहाँ विविधता' की कमी परिलक्षित होती थी वहीं नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर 'सकते हैं।

वैकल्पिक विषयों के चयन के साथ साथ सबसे अधिक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं रोजगार की संभावनाओं का द्वार खोलने वाला कदम है । व्यावसायिक विषय (Vocational Course) योग्यता संवर्धन आधार पाठ्यक्रम एवं व्यावहारिक ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए फील्ड प्रोजेक्ट, इन्टर्नशिप, एप्रेन्टिसशिप एवं सामुदायिक जुड़ाव जैसे कार्य का चयन कर उसका अध्ययन करना इससे जहाँ विद्यार्थी सामाजिक उत्तरदायित्व को समझते है, वहीं व्यावसाय करने की अभिलाषा को पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ सकतेहै।

इन्टर्नशिप एवं फील्ड प्रोजेक्ट जैसे कार्य विद्यार्थी स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष से ही प्रारंभ कर देता है, जिससे वह अपनी रूचि एवं क्षमता केअनुरूप अपने भविष्य के लिए चयन कर रोजगार', स्व–रोजगार का सृजनकर्ता भी बन सकता है एवं स्टार्ट–अप की अवधारणा को मूर्त रुप प्रदान कर सकता है।

विद्यार्थियों मे व्यवसाय उन्मुखता में अभिवृद्धि करने उनमें कौशल संवर्द्धन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक विषयों के समूह मे से किसी एक का चयन करना अनिवार्य है।

म.प्र. शासनके उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लागू की गई नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रचुर मात्रा में व्यावसायिक विषय रखे गये हैं। इन विषयों को महाविद्यालय में उपलब्धता पर या भारत 'सरकार के SWAYAM Portal अथवा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से भी विद्यार्थी अध्ययन कर सकते हैं ।

प्रमुख व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो बेहद उपयोगी एवं रोजगारपरक है जैसे– सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण, औषधीय पौधे, पोषण एवं आहार विज्ञान, निर्यात आयात प्रबंधन, जीएसटी के साथ ई.अकाउंटिंग और कराधान वित्त सेवाएँ और बीमा, रिटेल मेनेजमेण्ट, डिजिटल मार्केटिंग, बिक्री कौशल (सेल्समेनि ाप अकाउंटिंग एवं टैली कोर्स, डेस्कटॉप पब्लि िंग इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प (हैडीक्राफ्ट) खाद्यसंरक्षण और प्रसंस्करण, जैविक खेती, बागवानी, सुरक्षा सेवाएं, कार्यालय प्रक्रिया और व्यवहार, व्यक्तित्व विकास, पर्यटन परिवहन और यात्रा सेवाएँ, वर्मी कम्पोस्टिंग एवं डेयरी प्रबंधन।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन विद्यार्थी के लिए शिक्षा के साथ साथ ज्ञानअर्जन एवं रोजगार की विश्वसनीयता बढ़ेगी। जहां पहले विद्यार्थी विद्याध्ययन के पश्चात प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से मात्र सरकारी नौकरियों पर ही निर्भर रहता था, वही नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के साथ रोजगार, स्वं रोजगार के द्वार भी खोलेगी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के समक्ष एक समग्र व्यक्तित्व निर्माण का अवसर प्रदान करेगी। शिक्षा में विषयों में वैविध्य एवं अर्न्तविषयकता से विद्यार्थी को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकेगा, वहीं

प्रोजेक्ट कार्य में फील्ड प्रोजेक्टद्वारा नवोन्मेषी, नवाचार एवं शोध की प्रवृत्ति को उद्घाटित करने का अवसर उच्च शिक्षा के प्रथम सोपान से ही प्राप्त हो सकेगा ।

वही इन्टर्नशिप से अपनी पसंद केक्षेत्र मे जाकर व्यवसाय की संभावना एवं उसके प्राथमिक परिचय, संभावनाएं एवं चुनौतियों का कैसे सामना किया जाए, इसका ज्ञान हो सकेगा । यद्यपि राष्ट्रीय सेवा योजना एवं एन.सी.सी. द्वारा विद्यार्थी राष्ट्र सेवा एवं समाज सेवा से स्वयं को जोड़ पाता था, लेकिन एक विषय, एक अनुशासन के रूप में पहली बार राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) एवं एन.सी.सी. (N.C.C.) तथा फिज़ीकल एजुकेशन को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है।

फील्ड प्रोजेक्ट, इटर्नशिप के साथ विद्यार्थी सामुदायिक जुड़ाव (सेवा कार्य जिसे कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट प्रोग्राम भी कहते है वह करके सामाजिक सरोकार जैसे प्रौढ शिक्षा, बाल मजदूरी, आपदा प्रबंधन, वृद्धाश्रम जैसे कार्य से जुड़कर भविष्य में एक बेहतर नागरिक बन सकता है।

संक्षेप में, हम नवीन शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं को यूं रेखांकितकर सकते हैं।

गर्व का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सर्वप्रथम उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लागू कर दिया गया है

प्रमुख बिंदु –

1) विषय चयन में मुख्य/गौण एवं वैकल्पिक विषय चयन की स्वतंत्रता । जहाँ मुख्य या मेजर विद्यार्थी भविष्य में विद्यार्थी के लिए स्नातकोत्तर करने का आधार होगा साथ ही अपनी पसंद के अन्य विषयों में से विद्यार्थी गौण (माइनर) एवं वैकल्पिक (इलेक्टिव) विषय का चयन कर सकता है।

   राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, में सबसे नवीन एवं क्रांतिकारी बदलाव वाली जो बात है वह ये है कि अब विज्ञान/वाणिज्य एवं कला का विद्यार्थी ओपन इलेक्टिव में अन्य संकाय का विषय भी ले सकता है जो पहले संभव नहीं था। जैसे विज्ञान का विद्यार्थी हिन्दी में अनुवाद विज्ञान का अध्ययन कर सकता है।
2) प्राचीन भारतीय संस्कृति से संपन्न समावेशी शिक्षा– ब्रिटिश या मुगलकाल के दौर मे ज्ञान के जो कहीं दब गये थे उन प्राचीन सांस्कृतिक ज्ञान परम्परा का पुनः अध्ययन इस शिक्षा नीति में समाविष्ट किया गया है जैसे रामचरितमानस का एक – अध्ययन ।
3) व्यावसायिक शिक्षा का स्नातक स्तर के प्रथम सोपान पर समावेश.–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महत्वपूर्ण नवाचार यही है किसी एक व्यावसायिक पाठ्याक्रम का अध्ययन विद्यार्थी के लिए आवश्यक कर दिया गया है, ताकि वह विद्याध्ययन के साथ रोजगार के लिए भी तैयार हो सके।

4) योग्यता संवर्धन शिक्षा नीति – पारंपरिक शिक्षा के साथ–साथ भाषा विज्ञान, योग एवं ध्यान, पर्यावरण जैसे विषय बेहद उपयोगी है।
5) लचीली शिक्षा व्यवस्था –राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विषय की विभाजन रेखा को मिटा 'दिया है, वही चयन के लिए प्रचुर 'विकल्प प्रदान किये है। आगम– निर्गम व्यवस्था भी नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति मे उपलब्ध करा दी है। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री एवं डिग्री विद् रिसर्च की भी व्यवस्था है।
6) ऑनलाइन सुविधा :– विद्यार्थियों को जो पाठ्याक्रम महाविद्यालयों मे उपलब्ध नहीं हो रहे है वे भारत सरकार स्वयं पोर्टल या मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं के संसाधनों से भी पूर्ण कर सकते है।
7) चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम
8) बहुविषयक शिक्षा
9) परिणाम आधारित शिक्षा एवं पाठ्याक्रम
10) बहुआगमन एवं निर्गमन व्यवस्था

अस्तु हम पाते हैं. कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को म.प्र. में लागू कर जहाँ उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के जीवन मे आमूलचूल परिवर्तन लाने का कार्य किया वही विद्यार्थियों का सर्वागीण विकास एवं रोजगार के द्वार खुलेंगे इसे भी निश्चित किया है ।

संदर्भ

नई शिक्षा नई उडान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन

ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

GOVERNMENT COLLEGE RAU-
INDORE

IMPACT OF NEW EDUCATION POLICY (NEP-2020) ON STUDENTS THEIR HOLISTIC DEVELOPMENT

DR. N. P. RAJPOOT*

ABSTRACT

IN THIS PAPER WE ANALYZED THAT THE HOLISTIC DEVELOPMENT OF STUDENTS THROUGH THE NEW EDUCATION POLICY IS EFFECTIVE DECISION OF DHE AND STATE GOVERNMENT.

Education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. Providing universal access to quality education is the key to India's continued ascent, and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice and equality, scientific advancement, national integration, and cultural preservation. Universal high-quality education is the best way forward for developing and maximizing our country's rich talents and resources for the good of the individual, the society, the country, and the world. India will have the highest population of young people in the world over the next decade, and our ability to provide high-quality educational opportunities to them will determine the future of our country. The global education development agenda reflected in the Goal 4 (SDG4) of the 2030 Agenda for

*Professor and hod of science
Govt. college rau- indore
Dated 14 august 2023

Introduction

Education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. Providing universal access to quality education is the key to India's continued ascent, and leadership on the global stage in terms of economic

growth, social justice and equality, scientific advancement, national integration, and cultural preservation. Universal high-quality education is the best way forward for developing and maximizing our country's rich talents and resources for the good of the individual, the society, the country, and the world. India will have the highest population of young people in the world over the next decade, and our ability to provide high-quality educational opportunities to them will determine the future of our country. The global education development agenda reflected in the Goal 4 (SDG4) of the 2030 Agenda.

The world is undergoing rapid changes in the knowledge landscape. With various dramatic scientific and technological advances, such as the rise of big data, machine learning, and artificial intelligence, many unskilled jobs worldwide may be taken over by machines, while the need for a skilled workforce, particularly involving mathematics, computer science, and data science, in conjunction with multidisciplinary abilities across the sciences, social sciences, and humanities, will be increasingly in greater demand. With climate change, increasing pollution, and depleting natural resources, there will be a sizeable shift in how we meet the world's energy, water, food, and sanitation needs, again resulting in the need for new skilled labour, particularly in biology, chemistry, physics, agriculture, climate science, and social science. The growing emergence of epidemics and pandemics will also call for collaborative research in infectious disease management and development of vaccines and the resultant social issues heightens the need for multidisciplinary learning. There will be a growing demand for humanities and art, as India moves towards becoming a developed country as well as among the three largest economies in the world. Indeed, with the quickly changing employment landscape and global ecosystem, it is becoming increasingly critical that children not only learn, but more importantly learn how to learn. Education thus, must move towards less content, and more towards learning about how to think critically and solve problems, how to be creative and multidisciplinary, and how to innovate, adapt, and absorb new material in novel and changing fields. Pedagogy must evolve to make education more experiential, holistic, integrated, inquiry-driven, discovery-oriented, learner-centred, discussion-based, flexible, and, of course, enjoyable. The curriculum must include basic arts, crafts, humanities, games, sports and fitness, languages, literature, culture, and values, in addition to science and mathematics, to develop all aspects and capabilities of learners; and make education more well-rounded, useful, and fulfilling to the learner. Education must build character, enable learners to be ethical, rational,

compassionate, and caring, while at the same time prepare them for gainful, fulfilling employment.

1. PRINCIPLES OF THIS POLICY

The purpose of the education system is to develop good human beings capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and 4 National Education Policy 2020 creative imagination, with sound ethical moorings and values. It aims at producing engaged, productive, and contributing citizens for building an equitable, inclusive, and plural society as envisaged by our Constitution. A good education institution is one in which every student feels welcomed and cared for, where a safe and stimulating learning environment exists, where a wide range of learning experiences are offered, and where good physical infrastructure and appropriate resources conducive to learning are available to all students. Attaining these qualities must be the goal of every educational institution. However, at the same time, there must also be seamless integration and coordination across institutions and across all stages of education. The fundamental principles that will guide both the education system at large, as well as the individual institutions within it are:

• Recognizing, identifying, and fostering the unique capabilities of each student, by sensitizing teachers as well as parents to promote each student's holistic development in both academic and non-academic spheres;

- According the highest priority to achieving Foundational Literacy and Numeracy by all students by Grade 3;
- Flexibility, so that learners have the ability to choose their learning trajectories and programmes, and thereby choose their own paths in life according to their talents and interests;
- No hard separations between arts and sciences, between curricular and extra-curricular activities, between vocational and academic streams, etc. in order to eliminate harmful hierarchies among, and silos between different areas of learning; Multidisciplinary and a holistic education across the sciences, social sciences, arts, humanities, and sports for a multidisciplinary world in order to ensure the unity and integrity of all knowledge.
- Emphasis on conceptual understanding rather than rote learning and learning-for-exams;
- Creativity and critical thinking to encourage logical decision-making and innovation;

- Ethics and human & Constitutional values like empathy, respect for others, cleanliness, courtesy, democratic spirit, spirit of service, respect for public property, scientific temper, liberty, responsibility, pluralism, equality, and justice;
- Promoting multilingualism and the power of language in teaching and learning;
- Life skills such as communication, cooperation, teamwork, and resilience;
- Focus on regular formative assessment for learning rather than the summative assessment that encourages today's 'coaching culture
- Extensive use of technology in teaching and learning, removing language barriers, increasing access for Divyang students, and educational planning and management
- Respect for diversity and respect for the local context in all curriculum, pedagogy, and policy, always keeping in mind that education is a concurrent subject;
- Full equity and inclusion as the cornerstone of all educational decisions to ensure that all students are able to thrive in the education system;
- Synergy in curriculum across all levels of education from early childhood care and education to school education to higher education;
- Teachers and faculty as the heart of the learning process – their recruitment, continuous professional development, positive working environments and service conditions;
- A 'light but tight' regulatory framework to ensure integrity, transparency, and resource efficiency of the educational system through audit and public disclosure while encouraging innovation and out-of-the-box ideas through autonomy, good governance, and empowerment;
- Outstanding research as a corequisite for outstanding education and development;
- Continuous review of progress based on sustained research and regular assessment.

2. THE VISON OF THIS POLICY

This National Education Policy envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat, sustainably into an equitable and vibrant knowledge society, by providing high-quality education to all, and thereby making India a global knowledge superpower. The Policy envisages that the curriculum and pedagogy of our institutions must develop among the students a deep sense of respect towards the Fundamental Duties and Constitutional values, bonding with one's country, and a conscious awareness of one's roles and responsibilities in a changing world. The vision of the Policy is to instil among the learners a deep-rooted pride in being Indian, not only in thought, but also in

spirit, intellect, and deeds, as well as to develop knowledge, skills, values, and dispositions that support responsible commitment to human rights, sustainable development and living, and global well-being, thereby reflecting a truly global citizen. Part I. SCHOOL EDUCATION This policy envisages that the extant 10+2 structure in school education will be modified with a new

3. Curtailing Dropout Rates and Ensuring Universal Access to Education at All Levels

One of the primary goals of the schooling system must be to ensure that children are enrolled in and are attending school. Through initiatives such as the Sarva Shiksha Abhiyan (now the Samara Shiksha) and the Right to Education Act, India has made remarkable strides in recent years in attaining near-universal enrolment in elementary education. However, the data for later grades indicates some serious issues in retaining children in the schooling system. The GER for Grades 6-8 was 90.9%, while for Grades 9-10 and 11-12 it was only 79.3% and 56.5%, respectively - indicating that a significant proportion of enrolled students drop out after Grade 5 and especially after Grade 8. As per the 75th round household survey by NSSO in 2017-18, the number of out of school children in the age group of 6 to 17 years is 3.22 crore. It will be a top priority to bring these children back into the educational fold as early as possible, and to prevent further students from dropping out, with a goal to achieve 100% Gross Enrolment Ratio in preschool to secondary level by 2030. A concerted national effort will be made to ensure universal access and afford opportunity to all children of the country to obtain quality holistic education–including vocational education - from pre-school to Grade 12. 3.2. There are two overall initiatives that will be undertaken to bring children who have dropped out back to school and to prevent further children from dropping out. The first is to provide effective and sufficient infrastructure so that all students have access to safe and engaging school education at all levels from pre-primary school to Grade 12. Besides providing regular trained teachers at each stage, special care shall be taken to ensure that no school remains deficient on infrastructure support. The credibility of Government schools shall be re-established and this will be attained by upgrading and enlarging the schools that already exist, building additional quality schools in areas where they do not exist, and providing safe and practical conveyances and/or hostels, especially for the girl children, so that all children have the opportunity to attend a quality school and learn at the appropriate level. Alternative and innovative education centres will be put in place in cooperation with civil society to ensure that children of migrant

labourers, and other children who are dropping out of school due to various circumstances are brought back into mainstream education. 3.3. The second is to achieve universal participation in school by carefully tracking students, as well as their learning levels, in order to ensure that they (a) are enrolled in and attending school, and (b) have suitable opportunities to catch up and re-enter school in case they have fallen behind or dropped out. For providing equitable and quality education from the Foundational Stage through Grade 12 to all children up to the age of 18, suitable facilitating systems shall be put in place. Counsellors or well-trained social workers connected to schools/school complexes and teachers will continuously work with students and their parents and will travel through and engage with communities to ensure that all school-age children are attending and learning in school. Trained and qualified social workers from civil society organizations/departments of Social Justice and Empowerment and government functionaries dealing with empowerment of Persons with Disabilities at the State and district level, could be connected to schools, through various innovative mechanisms adopted by State/UT Governments, to help in carrying out this important work. Once infrastructure and participation are in place, ensuring quality will be the key in retention of students, so that they (particularly, girls and students from other socio-economically disadvantaged groups) do not lose interest in attending school. This will require a system of incentives for deploying teachers with knowledge of the local language to areas with high dropout rates, as well as overhauling the curriculum to make it more engaging and useful. 3.5. To facilitate learning for all students, with special emphasis on Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs), the scope of school education will be broadened to facilitate multiple pathways to learning involving both formal and non-formal education modes. Open and Distance Learning (ODL) Programmes offered by the National Institute of Open Schooling (NIOS) 10 National Education Policy 2020 and State Open Schools will be expanded and strengthened for meeting the learning needs of young people in India who are not able to attend a physical school. NIOS and State Open Schools will offer the following programmes in addition to the present programmes: A, B and C levels that are equivalent to Grades 3, 5, and 8 of the formal school system; secondary education programmes that are equivalent to Grades 10 and 12; vocational education courses/programmes; and adult literacy and life-enrichment programmes. States will be encouraged to develop these offerings in regional languages by establishing new/strengthening existing State Institutes of Open Schooling (SIOS). 3.6. To make it easier for both governments as well as non-governmental philanthropic organizations to build schools, to encourage local variations on account of culture, geography, and demographics, and to allow alternative models

of education, the requirements for schools will be made less restrictive. The focus will be to have less emphasis on input and greater emphasis on output potential concerning desired learning outcomes. Regulations on inputs will be limited to certain areas as enumerated in Chapter 8. Other models for schools will also be piloted, such as public-philanthropic partnerships. 3.7. Efforts will be made to involve community and alumni in volunteer efforts for enhancing learning by providing at schools: one-on-one tutoring; the teaching of literacy and holding of extra help sessions; teaching support and guidance for educators; career guidance and mentoring to students; etc. In this regard, the support of active and healthy senior citizens, school alumni and local community members will be suitably garnered. Databases of literate volunteers, retired scientists/government/semi government employees, alumni, and educators will be created for this purpose. Curriculum and Pedagogy in Schools: Learning Should be Holistic, Integrated, Enjoyable, and Engaging Restructuring school curriculum and pedagogy in a new 5+3+3+4 des

4. Holistic development of learners

The key overall thrust of curriculum and pedagogy reform across all stages will be to move the education system towards real understanding and towards learning how to learn – and away from the culture of rote learning as is largely present today. The aim of education will not only be cognitive development, but also building character and creating holistic and well-rounded individuals equipped with the key 21st century skills. Ultimately, knowledge is a deep-seated treasure and education helps in its manifestation as the perfection which is already within an individual. All aspects of curriculum and pedagogy will be reoriented and revamped to attain these critical goals. Specific sets of skills and values across domains will be identified for integration and incorporation at each stage of learning, from pre-school to higher education. Curriculum frameworks and transaction mechanisms will be developed for ensuring that these skills and values are imbibed through engaging processes of teaching and learning. NCERT will identify these required skill sets and include mechanisms for their transaction in the National Curriculum Framework for early childhood and school education.

5. Experiential learning

In all stages, experiential learning will be adopted, including hands-on learning, arts-integrated and sports-integrated education, story-telling-based pedagogy, among others, as standard pedagogy within each subject, and with explorations of relations among different subjects. To

close the gap in achievement of learning outcomes, classroom transactions will shift, towards competency-based learning and education. The assessment tools (including assessment "as", "of", and "for" learning) will also be aligned with the learning outcomes, capabilities, and dispositions as specified for each subject of a given class. 4.7. Art-integration is a cross-curricular pedagogical approach that utilizes various aspects and forms of art and culture as the basis for learning of concepts across subjects. As a part of the thrust on experiential learning, art-integrated education will be embedded in classroom transactions not only for creating joyful classrooms, but also for imbibing the Indian ethos through integration of Indian art and culture in the teaching and learning process at every level. This art-integrated approach will strengthen the linkages between education and culture. 4.8. Sports-integration is another cross-curricular pedagogical approach that utilizes physical activities including indigenous sports, in pedagogical practices to help in developing skills such as collaboration, self-initiative, self-direction, self-discipline, teamwork, responsibility, citizenship, etc. Sports-integrated learning will be undertaken in classroom transactions to help students adopt fitness as a lifelong attitude and to achieve the related life skills along with the levels of fitness as envisaged in the Fit India Movement. The need to integrate sports in education is well recognized as it serves to 12 National Education Policy 2020 foster holistic development by promoting physical and psychological well-being while also enhancing cognitive abilities. Empower students through flexibility in course choices 4.9. Students will be given increased flexibility and choice of subjects to study, particularly

6. **Empower students through flexibility in course choices**

Students will be given increased flexibility and choice of subjects to study, particularly in secondary school - including subjects in physical education, the arts and crafts, and vocational skills – so that they can design their own paths of study and life plans. Holistic development and a wide choice of subjects and courses year to year will be the new distinguishing feature of secondary school education. There will be no hard separation among 'curricular', 'extracurricular' , or 'co-curricular', among 'arts', 'humanities', and 'sciences', or between 'vocational' or 'academic' streams. Subjects such as physical education, the arts and crafts, and vocational skills, in addition to science, humanities, and mathematics, will be incorporated throughout the school curriculum, with a consideration for what is interesting and safe at each age. 4.10. Each of the four stages of school education, in accordance with what may be possible in different regions, may consider moving towards a semester or any other system that allows

the inclusion of shorter modules, or courses that are taught on alternate days, in order to allow an exposure to more subjects and enable greater flexibility. States may look into innovative methods to achieve these aims of greater flexibility and exposure to and enjoyment of a wider range of subjects, including across the arts, sciences, humanities, languages, sports, and vocational subjects. Multilingualism and the power of language 4.11. It is well understood that young children learn and grasp nontrivial concepts more quickly in

7. Essential Subjects, Skills, and Capacities in curriculum

While students must have a large amount of flexibility in choosing their individual curricula, certain subjects, skills, and capacities should be learned by all students to become good, successful, innovative, adaptable, and productive human beings in today's rapidly changing world. In addition to proficiency in languages, these skills include: scientific temper and evidence-based thinking; creativity and innovativeness; sense of aesthetics and art; oral and written communication; health and nutrition; physical education, fitness, wellness, and sports; collaboration and teamwork; problem solving and logical reasoning; vocational exposure and skills; digital literacy, coding, and computational thinking; ethical and moral reasoning; knowledge and practice of human and Constitutional values; gender sensitivity; Fundamental Duties; citizenship skills and values; knowledge of India; environmental awareness including water and resource conservation, sanitation and hygiene; and current affairs and knowledge of critical issues facing local communities, States, the country, and the world. . Concerted curricular and pedagogical initiatives, including the introduction of contemporary subjects such as Artificial Intelligence, Design Thinking, Holistic Health, Organic Living, Environmental Education, Global Citizenship Education (GCED), etc. at relevant stages will be undertaken to develop these various important skills in students at all levels. It is recognized that mathematics and mathematical thinking will be very important for India ' s future and India's leadership role in the numerous upcoming fields and professions that will involve artificial intelligence, machine learning, and data science, etc. Thus, mathematics and computational thinking will be given increased emphasis throughout the school years, starting with the foundational stage, through a variety of innovative methods, including the regular use of puzzles and games that make mathematical thinking more enjoyable and engaging. Activities involving coding will be introduced in Middle Stage. 15 National Education Policy 2020.

8. IN HIGHER EDUCATION PERSPECTIVE

Quality Universities and Colleges: A New and Forward-looking Vision for India's Higher Education System . Higher education plays an extremely important role in promoting human as well as societal wellbeing and in developing India as envisioned in its Constitution – a democratic, just, socially conscious, cultured, and humane nation upholding liberty, equality, fraternity, and justice for all. Higher education significantly contributes towards sustainable livelihoods and economic development of the nation. As India moves towards becoming a knowledge economy and society, more and more young Indians are likely to aspire for higher education. Given the 21st century requirements, quality higher education must aim to develop good, thoughtful, well-rounded, and creative individuals. It must enable an individual to study one or more specialized areas of interest at a deep level, and also develop character, ethical and Constitutional values, intellectual curiosity, scientific temper, creativity, spirit of service, and 21st century capabilities across a range of disciplines including sciences, social sciences, arts, humanities, languages, as well as professional, technical, and vocational subjects. A quality higher education must enable personal accomplishment and enlightenment, constructive public engagement, and productive contribution to the society. It must prepare students for more meaningful and satisfying lives and work roles and enable economic independence. For the purpose of developing holistic individuals, it is essential that an identified set of skills and values will be incorporated at each stage of learning, from pre-school to higher education. At the societal level, higher education must enable the development of an enlightened, socially conscious, knowledgeable, and skilled nation that can find and implement robust solutions to its own problems. Higher education must form the basis for knowledge creation and innovation thereby contributing to a growing national economy. The purpose of quality higher education is, therefore, more than the creation of greater opportunities for individual employment. It represents the key to more vibrant, socially engaged, cooperative communities and a happier, cohesive, cultured, productive, innovative, progressive, and prosperous nation. Some of the major problems currently faced by the higher education system in India include: (a) a severely fragmented higher educational ecosystem; (b) less emphasis on the development of cognitive skills and learning outcomes; (c) a rigid separation of disciplines, with early specialisation and streaming of students into narrow areas of study; (d) limited access particularly in socio-economically disadvantaged areas, with few HEIs that teach in local languages (e) limited teacher and institutional autonomy; (f) inadequate mechanisms for merit-based career

management and progression of faculty and institutional leaders; (g) lesser emphasis on research at most universities and colleges, and lack of competitive peer reviewed research funding across disciplines; (h) suboptimal governance and leadership of HEIs; (i) an ineffective regulatory system; and (j) large affiliating universities resulting in low standards of undergraduate education. 33 National Education Policy 2020 9.3. This policy envisions a complete overhaul and re-energising of the higher education system to overcome these challenges and thereby deliver high-quality higher education, with equity and inclusion. The policy's vision includes the following key changes to the current system: (a) moving towards a higher educational system consisting of large, multidisciplinary universities and colleges, with at least one in or near every district, and with more HEIs across India that offer medium of instruction or programmes in local/Indian languages; (b) moving towards a more multidisciplinary undergraduate education; (c) moving towards faculty and institutional autonomy; (d) revamping curriculum, pedagogy, assessment, and student support for enhanced student experiences; (e) reaffirming the integrity of faculty and institutional leadership positions through merit appointments and career progression based on teaching, research, and service; (f) establishment of a National Research Foundation to fund outstanding peer-reviewed research and to actively seed research in universities and colleges; (g) governance of HEIs by high qualified independent boards having academic and administrative autonomy; (h) "light but tight" regulation by a single regulator for higher education; (i) increased access, equity, and inclusion through a range of measures, including greater opportunities for outstanding public education; scholarships by private/philanthropic universities for disadvantaged and underprivileged students; online education, and Open Distance Learning (ODL); and all infrastructure and learning materials accessible and available to learners with disabilities. Institutional Restructuring and Consolidation. The main thrust of this policy regarding higher education is to end the fragmentation of higher education by transforming higher education institutions into large multidisciplinary universities, colleges, and HEI clusters/Knowledge Hubs, each of which will aim to have 3,000 or more students. This would help build vibrant communities of scholars and peers, break down harmful silos, enable students to become well-rounded across disciplines including artistic, creative, and analytic subjects as well as sports, develop active research communities across disciplines including cross-disciplinary research, and increase resource efficiency, both material and human, across higher education. 10.2. Moving to large multidisciplinary universities and HEI clusters is thus the highest recommendation of this policy regarding the structure of higher education. The ancient Indian universities Takshashila,

Nalanda, Vallabhi, and Vikramshila, which had thousands of students from India and the world studying in vibrant multidisciplinary environments, amply demonstrated the type of great success that large multidisciplinary research and teaching universities could bring. India urgently needs to bring back this great Indian tradition to create well-rounded and innovative individuals, and which is already transforming other countries educationally and economically. This vision of higher education will require, in particular, a new conceptual perception/understanding for what constitutes a higher education institution (HEI), i.e., a university or a college. A university will mean a multidisciplinary institution of higher learning that offers undergraduate and graduate programmes, with high quality teaching, research, and community engagement. The definition of university will thus allow a spectrum of institutions that range from those that place equal emphasis on teaching and research i.e., Research-intensive Universities, those that place greater emphasis on teaching but still conduct significant research i.e. Teaching-intensive Universities; governance reforms; financial robustness; and administrative efficiency. All colleges currently affiliated to a university shall attain the required benchmarks over time to secure the prescribed accreditation benchmarks and eventually become autonomous degree-granting colleges. This will be achieved through a concerted national effort including suitable mentoring and governmental support for the same. The overall higher education sector will aim to be an integrated higher education system, including professional and vocational education. This Policy and its approach will be equally applicable to all HEIs across all current streams, which would eventually merge into one coherent ecosystem of higher education. University, worldwide, means a multidisciplinary institution of higher learning that offers undergraduate, graduate, and Ph.D programmes, and engages in high-quality teaching and research. The present complex nomenclature of HEIs in the country such as 'deemed to be university', 'affiliating university', 'affiliating technical university', 'unitary university' shall be replaced simply by 'university' on fulfilling the criteria as per norms. Towards a More Holistic and Multidisciplinary Education. India has a long tradition of holistic and multidisciplinary learning, from universities such as Takshashila and Nalanda, to the extensive literatures of India combining subjects across fields. Ancient Indian literary works such as Banabhatta's Kadambari described a good education as knowledge of the 64 Kalaas or arts; and among these 64 'arts' were not only subjects, such as singing and painting, but also 'scientific 'fields, such as chemistry and mathematics, 'vocational ' fields such as carpentry and clothes-making, 'professional 'fields, such as medicine and engineering, as well as ' soft skills' such as communication, discussion, and debate. The very idea that all branches of creative

human endeavour, including mathematics, science, vocational subjects, professional subjects, and soft skills should be considered 'arts', has distinctly Indian origins. This notion of a ' knowledge of many arts' or what in modern times is often called the 'liberal arts' (i.e., a liberal notion of the arts) must be brought back to Indian education, as it is exactly the kind of education that will be required for the 21st century. Assessments of educational approaches in undergraduate education that integrate the humanities and arts with Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) have consistently showed positive learning outcomes, including increased creativity and innovation, critical thinking and higher-order thinking capacities, problem-solving abilities, teamwork, communication skills, more in depth learning and mastery of curricula across fields, increases in social and moral awareness, etc., besides general engagement and enjoyment of learning. Research is also improved and enhanced through a holistic and multidisciplinary education approach. A holistic and multidisciplinary education would aim to develop all capacities of human beings -intellectual, aesthetic, social, physical, emotional, and moral in an integrated manner. Such an education will help develop well-rounded individuals that possess critical 21st century capacities in fields across the arts, humanities, languages, sciences, social sciences, and professional, technical, and vocational fields; an ethic of social engagement; soft skills, such as communication, discussion and debate; and rigorous specialization in a chosen field or fields. Such a holistic education shall be, in the long term, the approach of all undergraduate programmes, including those in professional, technical, and vocational disciplines. 36 National Education Policy 2020. A holistic and multidisciplinary education, as described so beautifully in India ' s past, is indeed what is needed for the education of India to lead the country into the 21st century and the fourth industrial revolution. Even engineering institutions, such as IITs, will move towards more holistic and multidisciplinary education with more arts and humanities. Students of arts and humanities will aim to learn more science and all will make an effort to incorporate more vocational subjects and soft skills. Imaginative and flexible curricular structures will enable creative combinations of disciplines for study, and would offer multiple entry and exit points, thus, removing currently prevalent rigid boundaries and creating new possibilities for life-long learning. Graduate-level, master's and doctoral education in large multidisciplinary universities, while providing rigorous research-based specialization, would also provide opportunities for multidisciplinary work, including in academia, government, and industry. Large multidisciplinary universities and colleges will facilitate the move towards high-quality holistic and multidisciplinary education. Flexibility in curriculum and novel and engaging course options will be on offer to students, in

addition to rigorous specialization in a subject or subjects. This will be encouraged by increased faculty and institutional autonomy in setting curricula. Pedagogy will have an increased emphasis on communication, discussion, debate, research, and opportunities for cross-disciplinary and interdisciplinary thinking. Departments in Languages, Literature, Music, Philosophy, Indology, Art, Dance, Theatre, Education, Mathematics, Statistics, Pure and Applied Sciences, Sociology, Economics, Sports, Translation and Interpretation, and other such subjects needed for a multidisciplinary, stimulating Indian education and environment will be established and strengthened at all HEIs guides. 12.4. Third, students from socio-economically disadvantaged backgrounds require encouragement and support to make a successful transition to higher education. Universities and colleges will thus be required to set up high-quality support centres and will be given adequate funds and academic resources to carry this out effectively. There will also be professional academic and career counselling available to all students, as well as counsellors to ensure physical, psychological and emotional well-being. Fourth, ODL and online education provide a natural path to increase access to quality higher education. In order to leverage its potential completely, ODL will be renewed through concerted, evidence-based efforts towards expansion while ensuring adherence to clearly articulated standards of quality. ODL programmes will aim to be equivalent to the highest quality in-class programmes available. Norms, standards, and guidelines for systemic development, regulation, and accreditation of ODL will be prepared, and a framework for quality of ODL that will be recommendatory for all HEIs will be developed. 12.6. Finally, all programmes, courses, curricula, and pedagogy across subjects, including those in class, online, and in ODL modes as well as student support will aim to achieve global standards of quality.

9. CONCLUSION OF POLICY

Subject-wise implementation committees of experts in cooperation and consultation with other relevant Ministries will be set up at both the Central and State levels to develop detailed implementation plans for each aspect of this Policy in accordance with the above principles to achieve the goals of the Policy in a clear and phased manner. Yearly joint reviews of the progress of implementation of the policy, in accordance with the targets set for each action, will be conducted by designated teams constituted by MHRD and the States, and reviews will be shared with CABE.

In the decade of 2030–40, the entire policy will be in an operational mode, following which another comprehensive review will be undertaken

ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

वर्तमान परिदृश्य में नई शिक्षा नीति की चुनौतियां एवं सुझाव (एक वर्णनात्मक अध्ययन)

रेखा वर्मा
सहा. प्राध्यापक अर्थशास्त्र

प्रस्तावना

शिक्षा प्रणाली में शिक्षा नीति वह है जिसके अंदर सिद्धांत एवं कानूनों का समुच्चय होता है इस नीति के अनुसार शिक्षा का प्रसार किया जाता है शिक्षा समाज को दिशा प्रदान करती है जिससे समाज को गति मिल सके और इस काम के लिए शिक्षा ही माध्यम बनती है इसे हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि शिक्षा नीति वह है जिसमें शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सिद्धांत एवं कानूनों का समुच्चय बनाया जाता हैनई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को अस्तित्व में आई कुल 34 वर्ष के अन्तराल में शिक्षा नीति में बदलाव किए गए। जिससे बेहतर समाज का निर्माण हो सके और देश मे सभी को जीवन का उच्चतम स्तर प्राप्त हो सके इसके लिए तत्कालीन समय में समाज और देश की बेहतरी के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार किये इसके लिए पुरातन पद्धति का अध्ययन आवश्यक हो जाता है जिससे हम आज के परिप्रेक्ष्य की चुनौतियां को समझ सके और वर्तमान में मौलिक विशेषताओं पर ध्यान दे सके शिक्षित व्यक्ति समाज में किस तरह का आचरण करे एवं शिक्षित व्यक्ति समाज में किस तरह का मनन करे यही उच्चशिक्षा की कसौटी होती है। शिक्षा यदि ज्ञान केंद्रित ना होकर मूल्य केंद्रित होती है तो उससे व्यक्तित्त्व पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार नई शिक्षा नीति ने शिक्षा में होने वाले नए प्रयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही है और शिक्षक एवं विद्यार्थीदोनों का महत्वपूर्ण एवं अनूकुल वातावरण तैयार करके कार्य करने के लिए प्रेरित करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समसामयिक वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप प्रावधान किए गए है। विद्यार्थियों में शिक्षा का विकास हो एवं उनमे कौशल संवर्धन की प्रक्रिया तेज हो सके इस व्यवस्था को नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है इसे व्यवहारिक एवं उद्देश्य परक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं इस शिक्षा नीति में शामिल किया गया है इससे व्यवहारिक एवं उद्देश्य परक शिक्षा का महौल बनाया जाना आवश्यक है इससे विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी एवं

विद्यार्थियों को शिक्षा प्रशिक्षण का केंद्र मानकर इस शिक्षा प्रणाली को गति दी जा रही है

नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक प्राथमिक स्कूलिंग से माध्यमिक स्तर तक जीईआर को 100: तक बढ़ाना है जबकि व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चशिक्षा में जी आई आर 50: तक बढ़ाना है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत बनाई जा रही शिक्षा नीति को मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाता है लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद इस मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया एवं शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों की मदद से सकल घरेलू उत्पाद का 6: हिस्सा व्यय करने का लक्ष्य निधारित किया गया है। नई शिक्षा नीति चार स्तम्भों पर अधारित है जो ऐक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी और एकाउंटेबिलिटी पर आधारित है इस नीति में 5+3+3+4 संरचना होगी यह 10+2 ढांचे को बदल देगा।

जब देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह मौलिक अधिकार बन गया। लेकिन धीरे धीरे यह चुनौतियों का अंबार बनता जा रहा है उन सभी उपायों की तलाश लगातार जारी है जिससे इस क्षेत्र मे क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है मानव विकास का मूलमंत्र शिक्षा है जो देश के देश के सामाजिक आर्थिक तंत्र के संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है लेकिनस्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी शिक्षा प्रणाली अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ दिखाई देता है

वर्तमान शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियां :–

- शिक्षा समवर्ती विषय होने के कारण राज्यों के अपने बोर्ड है इसके समन्वय के लिए राज्यों को आगे आना होगा एकल परिषद के लिए राज्यों को साधन संपन्न बनाना होगा ।
- नई शिक्षा नीति में विदेशी के विश्वविद्यालयों में पढ़ने का प्रावधान किया गया है जिससे शिक्षा महंगी हो सकती है इससे निम्न वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा चुनौती से पूर्ण हो सकती है।
- दक्षिण के राज्यों जिसमे भाषाई चुनौतियां है उनके लिए किए जाने वाले सुधारों के असफल होने का जोखिम बना हुआ है

- बजट को लेकर आशंका जतायी जा रही है मुनाफाखोरी में अंकुश लगाने के लिए नियामक प्राधिकरण को काफी मेहनत करनी पड़ेगी।
- मानवसंसाधन की प्रतिपूर्ति भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। चूकी हमारे देश का शिक्षा क्षेत्र अच्छे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षको की कमी से जूझ रहा है।
- भारत में उच्चशिक्षा में गुणवत्ता एक बहुत बड़ी चुनौती है टॉप 200 विश्व रेकिग में बहुत कम भारतीय संस्थानों को जगह मिल पा रही है

इन सभी चुनौतियों एवं समस्याओं को देखते हुए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते।

- सबसे पहले माध्यमिक स्तर की शिक्षा का सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर बच्चे का स्पष्ट आधार समाहित होता है इसे गुणवत्तापूर्ण बनाया जाना चाहिए।
- माध्यमिक स्तर पर ही शिक्षा के व्यावसायिक विषय में बदलाव किये जाने चाहिए इस स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण की नींव रखी जानी चाहिए।
- राष्ट्रीय शिक्षा मिशनकोमज़बूत किया किया जाना चाहिए इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का (ICT)का पूर्ण उपयोग होना चाहिए।
- शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षको की प्रशिक्षण व्यवस्था को सशक्त करना होगा।
- शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षको, अभिभावकों, सामुदायिक सदस्यों, विशेषज्ञों के सार्थक प्रयास की आवश्यकता होगी इस सुधार हेतु टीम इंडिया का गठन करना होगा।
- शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राविधियों में सुधार करने की जरूरत है शिक्षको के अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें वरिष्ठ और कर्तव्य निष्ठ एवं क्षमतावान प्रशिक्षित व्यक्तियों से प्रशिक्षण दिलवाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष –:

केंद्रीय मंत्री मंडल ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने एव मजबूत बनाने के लिए मंजूरी दे दी है यदि इस नीति को सही तरीके से क्रियान्वित किया जाता है

तो यह शिक्षा नीति भारत को विश्व पटल पर स्थान दे पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगी। किसी भी तरह के कार्यक्रम को लेकर आशंका तो होती है क्योंकि हमारादेश जनसंख्या के आधार पर भी बहुत विशाल है इसलिए शिक्षा नीति का मजबूत होना बहुत आवश्यक हो जाता है।

सन्दर्भ :–

The hindu 25 march 2019

http//nvshg.org>article

http//hindisarang.com

http //zedhindi.com

http//www.hindi.sscadda.com

ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आनलाइन प्रवेश : समस्याएं एवं सुझाव

जुली राठौर
कम्प्युटर ऑपरेटर
शासकीय महाविद्यालय राऊ, इन्दौर

सरकार की ओर से देश की शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) को लागू किया। इस नीति का मकसद देश में शिक्षा का विकास करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा पर जोर देती है। और इसका मुख्य उद्देश्य वयस्कों को अपने कौशल और ज्ञान को उन्नत करने के अवसर प्रदान करना है, जिससे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान मिलता रहे। सरकार की ओर से देश में शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के उद्देश से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश शिक्षा में गुणवत्ता का विकास करना है। इसी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वोकेशनल शिक्षा पर भी जोर दिया गया है इसके तहत आजीवन सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना और समय के साथ आने वाले चुनौतियों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना।

: ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया :

वर्तमान में प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में पंजियत उच्च शिक्षा की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए शासन द्वारा ऑनलाईन प्रवेश की प्रक्रिया लागू की गई है। प्रवेश की यह प्रक्रिया प्रदेश एवं अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी एवं सुविधा जनक है। ऑनलाईन प्रवेश के माध्यम से विद्यार्थी साइबर या स्वयं ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अपना प्रवेश रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। प्रवेश के प्रथम राउड में छात्राओं को निःशुल्क पंजियन से काफी आर्थिक लाभ मिलता है। जब विद्यार्थी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से विद्यार्थी एक बार स्नातक या स्नातकोत्तर की कक्षाओं के लिये पंजियत कर रजिस्टर्ड हो जाता है तब एक ही विद्यार्थी एक नाम से दो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है। ई–प्रवेश का एक लाभ यह भी है कि विद्यार्थियों को कॉलेज लेवल काउंसलिंग के लिए कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉलेज ऐडमिशन प्रवेश प्रक्रिया का एक मुख्य चरण तथा एक से अधिक शासन के निर्देशनुसार सीएलसी के चरण निर्धारित किए जाते हैं। विद्यार्थी महाविद्यालय चयन के लिये एक बार में अधिकतम 15 महाविद्यालय का चयन कर सकते हैं।

: ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के लाभ :

- प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में घर बैठे ही प्रवेश की प्राप्ति।
- विद्यार्थी की रूचि के अनुसार महाविद्यालय में चयन की सुविधा।

- विद्यार्थी की समय एवं धन की बचत।
- अधिभारों का प्रत्येक्ष लाभ जैसे NSS, NCC.

: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ई–प्रवेश की चुनौतियाँ :

मध्यप्रदेश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कॉलेज में ऑनलाईन प्रवेश लेने के लिये विद्यार्थियों को निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:–

- **ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी का आभाव :–** भारत एक ग्रामीण प्रधान देश होने से विशेषरूप से ग्रामीण अंचल के 12वीं पास करने के बाद विद्यार्थियों का महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिये ऑनलाई प्रवेश की प्रकिया की जान कारी नहीं होती है। जिससे कुछ विद्यार्थी कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पाते है।
- **रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की त्रुटियाँ :–** साईबर पर ऑनलाई रजिस्ट्रेशन फार्म भरते समय होने वाली त्रुटि जैसे विद्यार्थी का नाम, माता–पिता का नाम, जन्मतिथि, 12वीं के पूर्णाकं अंक एवं दस्तावेज जैसे अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, मूलनिवासी प्रमाणपत्र आदि को सहि तरह से डाउनलोड नहीं कर पाना।
- **त्रुटियाँ के सुधार में परेशनी :–** महाविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन फार्म के सत्यापन के वक्त किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर विद्यार्थी को त्रुटि की जान कारी के बाद त्रुटि सुधार में परेशनी।
- **धन की बर्बादी :–** यदि विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन फार्म में व्यक्तिगत जान कारी में कोई त्रुटि होती है तो उसे फॉर्म को निरस्त करवाना पड़ता है। जिससे विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन के समय जो पैसा दिया जाता है। डूब जाता है।
- **बार–बार चाईसफिलिंग की प्रक्रिया :–** एक बार में कॉलेज न मिलने के कारण विद्यार्थी बार–बार रिचाईस करवाता है जिससे उसके पैसा और समय दोनों ही बर्बात होता है।
- **निम्न % वालों के लिए प्रवेश लेने का अभाव :–** विद्यार्थियों को 12वीं 40 से 45 प्रतिशत होने के कारण विद्यार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाता है।
- **प्रवेश निरस्तीकरण पश्चात शुल्क वापस प्राप्त होने की समस्या :–** महाविद्यालय में विद्यार्थी के प्रवेश (1000रू.) होने के बाद किसी कारण वर्ष प्रवेश निरस्त करना चाहते है। लेकिन निरस्त नही हो पाता है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा के अनुरूप विषय चयन में समस्या :–** महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सीट ऑनलाईन के पश्चात विद्यार्थियों को विषयों के चयन जैसे मेजर, माइनर, ओपन, इलेक्टिव एवं वोकेशनल

सब्जेक्ट चुनने में परेशानी होती है। क्योंकि साईबर संचालक को प्रवेश प्रक्रिया एवं विषयों के चयन की पूर्ण जानकारी नहीं होती है।

: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव :

- **विद्यार्थियों को 12वीं परीक्षा के पूर्व विद्यालय द्वारा ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करना :–** विद्यार्थीयों को समाचर प्रत्र, स्कूलों में सूचना, एसएमएस वॉटस्प सूचना के माध्य से विद्यार्थियों जानकारी प्रदान की जाए जिससे विद्यार्थी समय पर प्रवेश के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सके।
- **ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हेतु पूर्वाभ्यास :–** साईबर पर ऑनलाई रजिस्ट्रेशन फार्म भरते समय त्रुटियाँ ना हो साईबर वालों का प्रवेश प्रकिया चालू होने से पहले प्रशिक्षण दिया जाए। और बताया जाये कि फॉर्म सबमिट के पहले विद्यार्थी को उसके एक प्रिंट दी जायें ताकि विद्यार्थी अपनी सारी जानकारी एक बार ठिक से देख सके।
- यदि महाविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन फार्म के सत्यापन में त्रुटि होने से शासन के द्वारा विद्यार्थी को एसएमएस संदेश के माध्यम से पूरी जानकारी दि जाये की त्रुटि क्या है जिससे विद्यार्थी उस त्रुटि का सुधार करवा सके।
- **बार–बार चाईसफिलिंग की प्रक्रिया से मुक्ति :–** यदि विद्यार्थी का प्रथम चरण में प्रवेश नहीं हो पाता तो उसे अगले चरण के लिये चाईसफिलिंग से मुक्त रखा जाना चाहिए। और उसका नाम स्वतह ही अगले चरण में सम्लित हो जाना चाहिए।
- **शुल्क वापसि का प्रावधानः–** यदि विद्यार्थी किसी कारण से स्वयं के प्रवेश को निरस्त कर वाना चाहता है। तो उसके द्वारा जमा किया गया शुल्क अविलंब विद्यार्थी के खाते में जमा हो जाना चाहिए।

संदर्भ :–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. https://www.jagran.com/news/education-madhya-pradesh-first-state-to-implement-national-education-policy-nep-2020-in-higher-education-minister-21924876.html

ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

विद्यार्थियों के समग्र विकास में पुस्तकालय की भूमिका– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में

ममता सोलंकी
पुस्तकालय सहायक
शासकीय महाविद्यालय राऊ, इन्दौर

शिक्षा के संबंध में गांधीजी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है इसी प्रकार स्वामी विवेकानंदजी का कहना था कि मनुष्य के अंतरनिहितपूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास में योगदान देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शालाओं के विकास पर अत्यधिक प्रकाश डाला गया है। जिसका उद्देश्य विद्यालय में शुरुआत की कक्षाओं से ही बच्चों में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करना है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना एवं सीखने की क्रिया परंतु शिक्षा का व्यापक अर्थ देखे तो शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिसका उद्देश्य ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा देश में स्कूल शिक्षा में अत्यधिक बल दिया गया है इसका उद्देश्य तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में सौ प्रतिशत के साथ–साथ पूर्व विद्यालय में से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिक का लक्ष्य रखा गया है।

शाला शिक्षा में पुस्तकालय का महत्व – पुस्तकालय विद्यालय का एक अभिन्न अंग है पुस्तकालय की विद्यार्थी के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए जो स्थान प्रयोगशाला का है तकनीकी विषयों के लिए जो स्थान कार्यशाला का है वही स्थान विद्यालय में विद्यार्थी के बौद्धिक तथा साहित्यिक ज्ञान की अभिवृद्धि करने के लिए पुस्तकालय का है।

पुस्तकालय के संबंध में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर रंगनाथनजी ने लिखा है कि जिस विद्यालय में परिवर्तन शील संसार के लिए शिक्षा दी जा रही है। उसके लिए पुस्तकालय एक वर्कशॉप के रूप में होता है।

विद्यार्थी के समग्र विकास में पुस्तकालय का योगदान –मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ब्रिटेन के पेम्पलेट डी स्कूल लाइब्रेरी में इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट तथा लाभदायक वक्तव्य स्पष्ट किया गया है कि पुस्तकालय शिक्षा का एक मुख्य साधन है। पुस्तकालय द्वारा विद्यार्थी में पुस्तकों के प्रति रुचि तथा उत्साह उत्पन्न किया जाता है जिसके फल स्वरुप विद्यार्थी के लिए ऐसे असंख्य मार्ग खुल जाते हैं जिसके द्वारा उसके बौद्धिक तथा मानसिक विकास में वृद्धि होती है। पुस्तकालय में विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ–साथ अन्य ज्ञान की पुस्तक समाचार पत्र उपलब्ध होते हैं जिनके द्वारा विद्यार्थी में नवाचार व संचार माध्यम में भी वृद्धि होती है। पुस्तकालय द्वारा विद्यार्थी में पढ़ने लिखने तथा बोलने की आदतों का विकास होता है पुस्तकालय द्वारा विद्यार्थियों में स्वाध्याय की रुचि उत्पन्न होती है जिसके फलस्वरुप उनका भौतिक विकास संभव होता है। पुस्तकालय द्वारा विद्यार्थी के ज्ञान का विस्तार होता है तथा आदर्शों का निर्माण होता है।

निष्कर्ष– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शाला शिक्षा एवं पुस्तकालय उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है एक विद्यालय का विकास तभी संभव होता है जब उस विद्यालय के पुस्तकालय विकसित होंगे इस हेतु पुस्तकालय प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होगी क्योंकि यदि गणित के शिक्षक को यदि हिंदी विषय पढ़ाने को कहा जाए तो वह उस विषय को अच्छे से सही तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे इस तरह पुस्तकालय हेतु एक पुस्तकालय प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होगी जो पुस्तकालय के सभी कार्यों में निपूर्ण हो और विद्यार्थियों को पुस्तकालय के बारे में सही जानकारी दें। इसके लिए पुस्तकालय अध्यक्ष को चाहिए कि वह समय–समय पर पुस्तकालय में कुछ ऐसी क्रियाएं करें जिससे कि विद्यार्थी कि पुस्तकालय के प्रति रुचि बड़े और वह अपना समय पुस्तकालय को दे। और अपने बौद्धिक विकास में वृद्धि कर देश का एक योग्य नागरिक बने।

ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – अवसर एवं चुनौतियां

डॉ. डी. सी. राठी
सहप्राध्यापक (वाणिज्य)
शासकीय महाविद्यालय राऊ, इन्दौर

म.प्र. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला अग्रणी प्रदेश है जहां सत्र 2020–21 से समस्त महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में इस नीति को लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति का एक बड़ा उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को संवारना और उन्हे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना है। विद्यार्थियों का सामना करने में सक्षम बनाना है। विद्यार्थियों को उस कौशल से लैस किया जाना चाहिए जिसके बिना आज के इस तकनीकी युग में काम चलने वाला नहीं है। इसलिए कौशल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

प्रमुख चुनौतियां –

1. नई शिक्षा नीति के तहत प्रमुख चुनौती विद्यार्थियों के वोकेशनल पाठ्यक्रम के तहत प्रायोगिक कार्य करवाने तथा फिल्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप कराने से संबंधित है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए ये कार्य कराना चुनौतिपूर्ण है। प्रायोगिक कार्य हेतु महाविद्यालय में आवश्यक संसाधन उपलब्ध न होने के कारण गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित नहीं हो पाता है। ठीक इसी प्रकार इंटर्नशिप के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को कम्पनियों में भेजना संभव नहीं हो पाता है। कई कम्पनियां सीमित संख्या में ही विद्यार्थियों को अनुमति प्रदान करती है।
   विद्यालयीन शिक्षा के अंतर्गत फिल्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप की व्यवस्था न होने के कारण प्रथम वर्ष के विद्यार्थी इनको अच्छे से समझ भी नहीं पाते है।
2. स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए भी प्रायोगिक कार्य तथा फिल्ड प्रोजेक्ट /इंटर्नशिप कराना अनिवार्य है। स्वाध्यायी परीक्षार्थी को जिस दिनांक तक परीक्षा फार्म भरना होता है उसके बाद इतना कम समय होता है कि विद्यार्थी इस कार्य को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व कर सकें। परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व तक विद्यार्थी परीक्षा फार्म भर सकते है। ऐसे में इन कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीकों से पूर्ण कराना संभव नहीं हो पाता है।
3. वोकेशनल पाठ्यक्रम के तहत संचालित विषयों में से कई विषयों की पुस्तके उपलब्ध नहीं है। साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इन विषयों की पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं हो पाती है।

4. देशभर के स्कूल तथा विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम समान नहीं है तथा कई राज्यों में नवीन शिक्षा नीति लागू नहीं है ऐसे में यदि कोई विद्यार्थी प्रथम या द्वितीय वर्ष की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद पारिवारिक कारणों से अन्य राज्य में पढ़ाई करने हेतु जाएगा तो उसे प्रवेश प्राप्त करने में समस्या होगी।

उक्त चुनौतियों का सामना करने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार करना उपयुक्त होगा –

1. स्नातक प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में फिल्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप की व्यवस्था स्नातक तृतीय वर्ष से लागू करना मेरी राय में उपयुक्त होगा। हां जब स्कूली शिक्षा में फिल्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप प्रारंभ होने पर इन्हे स्नातक प्रथम वर्ष से ही लागू किया जाना उपयुक्त होगा।
2. स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए वोकेशनल पाठ्यक्रम के तहत प्रायोगिक कार्य कि अनिवार्यतः को समाप्त किया जाना उपयुक्त होगा। साथ ही इनके लिए भी तृतीय वर्ष में ही फिल्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप की व्यवस्था किया जाना उपयुक्त होगा।
3. थोडे बहुत बदलाव के साथ सभी विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम अपनाएं जाए इसके लिए ठोस उपाय करने की आवश्यकता है।
4. महाविद्यालयों में वोकेशनल कोर्स के तहत प्रायोगशाला की व्यवस्था पृथक से हो तथा इस संबंध में प्राध्यापकों के विस्तृत प्रशिक्षण की व्यवस्था भी किया जाना उपुक्त होगा।
5. नई शिक्षा नीति के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु हायर सेकेन्डरी स्कूलों में अलग से एक प्रकोष्ठ हो। प्रकोष्ठ के माध्यम से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक/दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हो जिसमें स्थानीय स्तर के महाविद्यालयों से प्राध्यपकों को आमंत्रित कर नई शिक्षा नीति की जानकारी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाए ताकि स्नातक प्रथम वर्ष में ऑनलाइन प्रवेश के समय विद्यार्थियों कोई समस्या न हों।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति के तहत कई प्रकार की चुनौतियां है। स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति लागू हो जाने के पश्चात् इन चुनौतियों का सामना करने में आसानी होगी। साथ ही आवश्यक संसाधनों की महाविद्यालयों में उपलब्धता सुनिश्चित होने पर हम इन चुनौतियों को अवसर में बदल सकेंगें।

ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

NATIONAL EDUCATION POLICY (2020) AND ITS IMPLEMENTATION

Dr Jyoti Taneja

Department of English

SABV Government Arts and Commerce College, Indore

India has a vast education system with complexity of constituency it commands. To strengthen the base of curricula and to develop a scientific temper and evidence-based thinking together with aesthetics and art, the Indian government has drafted policies from time to time. The National Education Policy 2020 is in several and perfect ways what India needs in the present scenario, as it is developing into the world's largest workforce. It has replaced the old education policy which was framed in 1986 steering in an era of new educational reforms.

The New Education Policy is undoubtedly an aspiring, modern, progressive, and a futuristic education policy. This is the first policy that pursues to release students from limitations and allows them to expand with multiple-choice, multidisciplinary learning, and multiple chances. The said policy has also been predicted to reduce social and economic gap between students, which puffed up during the pandemic. It is also predicted that this policy will play a considerable role in dropping the number of educated unemployed individuals. Despite the all-encompassing fascia of the NEP 2020 which lays emphasis on making the education system holistic, flexible, and aligned to the needs of 21st-century education its success will have to overcome a few execution challenges constantly for years to come. It is a large-scale implementation which has never been tried anywhere before and hence will have to encounter certain trials whether they be qualitative or quantitative.

The policy is learner centric providing equal opportunities for growth, development, critical and creative thinking, improve communication, students will acquire the flair of teamwork, participation, cooperation, and practical skills for lifelong learning. Talking in terms of ourstate, the focus is on improving the quality of higher education along with its expansion. Still, the quality of education which NEP 2020 seeks to address, will have to face challenges.

The GOMP has joined hands with the World Bank to improve quality of higher education in the state and Madhya Pradesh Higher Education Quality improvement Project (MPHEQIP) – is a joint effort of it. The aim of the project is to improve the quality of education in government institutions, and to increase the effectiveness of the higher education system in Madhya Pradesh.

The policy has included vocational course to help students acquire the skills making higher education more practical-oriented, as they would need the same to succeed in the workplace in future. The government aims to bring our students to the forefront and be a part of the skilled workforce required in the market today. Internships, field projects are being promoted in universities and other higher educational institutions. In our state, Madhya Pradesh students come from backgrounds where they are dependent on certain occupations for many generations, it would work wonders if these vocational courses are based on the aptitude of the students.Vocational courses like gardening, pottery do not require infrastructure set ups and can be done in the college campusitself, but if fashion design, baking, handicrafts, colour wash, carpentry etc are to be included they may require a good setup for practical purposes. One of the major challenges regarding vocational training is the lack of proper resources. Hence vocational courses in HEIs will require infrastructure, set up and trained personnel and the question arises who will bear these additional costs because this requires high investment.

India is still far from achieving the target, and bridge the gap between what is required in the market and what we are giving, the target which was set by Kothari Commission in 1964-66 has not been achieved yet.Students will be exposed to a range of different subjects, including sciences, languages, commerce, and humanities.Inclusion of technology at all levels in education is another important feature of this policy this will help students and teachers participate in new and innovative learning experiences. There will be a need for significant financial resources to implement the same. Higher education institutes run by the government suffer from poor physical facilities and infrastructure. The higher education system also suffers from discrepancy in the sense that while there are courses in which the demand is in excess of the available number of seats, there is excess capacity in others.

For different subjects introduced, there is a shortage of faculty, there is also a challenge of providing quality education in remote and rural areas, and the need for effective collaboration between various stakeholders.Apart from poor infrastructure facilities, training the faculty, introducing, and planning a multidisciplinary curriculum, creating a new syllabus, and the huge costs involved in making the shift, will be a great crunch for the government.

The multiple entry and exit concept is very interesting but it can create an issue of saving records of the students who will join the institute any time and leave at any level. The policy states the formation of Academic Bank of Credit (ABC) to digitally store the academic credits received from different universities andinstitutes for the award of the degree whichis easy said than done. All this will take a lot of time, the credits earned will create a problem for keeping the track record, that was easy to recognize till now, from looking at the score card which student belonged to which stream. The universities and HEIs will have to work in sync and at a very fast pace.

There is a cost that universities will have to incur in terms of training the faculty also. Adequate financial resources for infrastructure, research, trainings are a must for a full-blown implementation of NEP 2020 in the state. For example, if there is an institution that is mainly a science institute and now to bring in multidiscipline subjects like history or economics need to be brought into it obviously the requirement of faculty will increase, involving a shift in the cost too. When we talk of faculty training it refers to upgrading the skills, knowledge, and professional competencies to enhance their teaching effectiveness. The policy has laid stress on the need for regular training and development programs to equip them with the latest knowledge and skills in their respective areas. The policy recommends that faculty should have access to workshops, and seminars to upgrade their skills and knowledge. To promote this, incentives for teachers and researchers will be required to keep the working faculty motivated and to attract younger generation into this profession.

According to the National Education Policy Draft Report by TSR Subramanian, the standard of education provided by many colleges are quite unsatisfactory. 40% of the college teachers work on a contractual basis or are appointed as guest faculty. The policy identifies the importance of research and innovation in education and has recommended the establishment of a National Research Foundation (NRF) to promote research in all fields but the details on how it will be funded are not clear. Faculty is encouraged to publish and go in

for research to become better contenders for promotion. However, the funds allocated from the resources available are very limited. For higher education, the maximum provision of government funds for research goes to the leading institutes, resulting in compromise on the quality of research and publications.

To conclude it is certain that the most important aspects of the successful implementation of NEP 2020 i.e., proper, and adequate infrastructure, capital, and a strategic plan are neverthelessmislaid. But, on a positive note, despite of the heavy investment required for future years, and other implementation challenges which also includes achievement of 6% GDP in education, digital literacy, trained teachers, infrastructure, and increase in the gross enrolment ratio to 50% by 2035, we should try to resolve the complications strategically and peacefully without getting discouraged from the hurdles with the hope for the best.

References

1..KRISHNA KUMAR, Quality of Education at the Beginning of the 21st Century – Lessons from India, Academia. August,20, 2023 https://www.academia.edu/44996146/Quality_of_Education_at_the_Beginning_of_the_21st_Century_Lessons_from_India

2.Banerjee T.&Jayasankara Reddy K. (2022). Status of Higher Education in India: Challenges, Issues and Opportunities. International Journal of Indian Psychology, 10(1), 430-439. DIP:18.01.040.20221001, DOI:10.25215/1001.040

3.https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/NEP_Final_English.pdf

4.https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/edutrends-india/nep-2020-empowering-the-teacher

ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

NATIONAL EDUCATION POLICY 2020: REFORMATION IN EDUCATION

Hemlata Thakur

Department of Mathematics, Government College Rau, Indore 453331, India

thakur.hem78@gmail.com

Abstract

The Union Cabinet of India approved the National Education Policy 2020 (NEP 2020) on July 29, 2020.This is the first education policy of the twenty-first century, replacing the 34-year-old National Policy on Education (NPE) of 1986.The policy intends to restructure the education system from pre-school through secondary level by 2030, with a 100% Gross Enrollment Ratio (GER) in school education.Some of the most significant reforms enacted by the NEP include teaching up to class five in the student's mother tongue or regional language, lowering the stakes of board exams, allowing foreign universities to establish campuses in India, establishing a single regulator for higher education institutions except for law and medical schools, and establishing common entrance exams for universities. The primary goal of the paper is to investigate the most significant improvements. The primary goal of this article is to investigate the most significant improvements and problems incorporated in NEP 2020. Methodology: This study is entirely qualitative, employing secondary data from books, journals, and websites, as well as research articles, government publications, and so on.

ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – प्रभावशीलता

डॉ. मालती सोलंकी
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
शासकीय महाविद्यालय राऊ, इन्दौर

शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना है। शिक्षा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में संपूर्ण विकास और उसमें स्वस्थ दृष्टिकोण एवं अच्छे संस्कार सम्मिलित करने में सहायक सिद्ध होती है। किसी भी देश के विकास में उसे देश में संचालित शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत एक ऐसा देश है, जहां शिक्षा को आदिकाल से ही महत्व दिया गया है। आजादी के बाद भारत में पहली नई शिक्षा नीति सन 1986 में बनाई गई थी,जो मुख्यतः लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी प्रधान शिक्षा नीति पर आधारित थी। सन 1986 में कुछ संशोधन भी किए गए, किंतु इसका ढांचा मूलतः अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पर ही केंद्रित रहा। किंतु आज के समय में धीरे–धीरे यह महसूस होने लगा कि पुरानी शिक्षा नीति में कुछ खामियां हैं इसमें विद्यार्थी ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है किंतु यह ज्ञान उसमें भविष्य में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने योग्य नहीं बना पा रहा है।

पिछले 34 वर्षों से हमारी शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया जबकि परिवर्तन विकास का आधार है। डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा परिवर्तन का साधन है, जो कार्य समाज में परिवार धार्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं द्वारा होता था वह आज शिक्षण संस्थान द्वारा किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर रोजगार मूलकता के महत्व के कारण आए परिवर्तनों को देखते हुए आज यह आवश्यक हो गया है कि सतत सीखने की कला के साथ शिक्षा के क्षेत्र में इस बात पर बल दिया जाए कि विद्यार्थी समस्या समाधान तार्किक एवं रचनात्मक रूप से चिंतन करना सीखें। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें तकनीकी, व्यवसायिक विज्ञान, गणित आदि विषयों के साथ कला शिल्प स्वास्थ्य साहित्य संस्कृति और मूल्य आदि समावेशित हो। विद्यार्थी रोजगार की दृष्टि से सक्षम तो बने ही उसमें नैतिकत, तार्किकता, चरित्र निर्माण एवं संवेदनशीलता आदि का विकास संभव हो। हमारी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसमें बेहतर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ विद्यार्थियों को सर्वोच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध हो सके। इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाने की आवश्यकता महसूस की गई। यह अत्यंत गौरव का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वित करने वाला देश में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है उच्च शिक्षा विभाग मात्र इस नीति को लागू करने तक ही सीमित नहीं है प्रदेश के विद्यार्थियों के समग्र एवं समेकित विकास की विस्तृत संकल्पनाओं के साथ लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में भी सतत रूप से अग्रसर है। हम अपने बाल्यकाल से ही ऐसी शिक्षा पद्धति की छत्रछाया में पले बढ़े हैं जिनमें सब विद्यार्थी एक दूसरे की देखा देखी कोर्स का चयन करते थे ना वह प्रतिभाओं का आकलन किया करते थे और ना ही अभिभावक की दूरदृष्टि इस और जाती थी या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल या चार्टर्ड अकाउंटेंट साधारण स्नातक होकर नौकरी ढूंढने की प्रथा थी पहले शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसी थी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवरोध उत्पन्न करती थी नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है कि छात्रों का संपूर्ण विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और वह भारत को सतत ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की दृष्टि से अति आवश्यक है।

ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

NATIONAL EDUCATION POLICY 2020 AND YOUTH EMPOWERMENT

Dr. Shweta Hardia,

Assistant Professor, Botany

Govt.College, Rau, Indore [M.P.]

Abstract

Youth and nation are symbiotically related to each other. Both depend on one another for their sustenance. The development of a nation is based on the education of its youth. India is now the most populous nation in the world with 1.486 billion people. The growth is driven by India's large, dynamic and young population, with 65% of Indians being under 35 years old. Therefore, one of the greatest challenges for governments and policymakers in India today is to provide opportunities for the youths so that they can have well organised lives and also can contribute tothe economic development of the country. The New Education Policy 2020 is such an initiative of government that will help in the empowerment of the youth for future challenges in the developing world. The New Education Policy will bring major changes in the present education system in India. This will lead to the path for the intellectual development of the youth in India. The government has taken this initiative to prepare the students for the challenges that they might have to face in the fast-changing world. The NEP 2020 will make youth better fitted for their future. The policy will not only educate youth but provides them a skill which they can use for their economic development. This will provide benefit to the whole country. The NEP-2020 will help youth to recognise the actual potential them. So it can be concluded that NEP-2020 will help youth in getting empowered with an ultimate goal of young, energised and developed nation.

Keywords: New Education Policy 2020, Youth, Empowerment, Youth Challenges

ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

LIBRARIES IN VIEW OF NATIONAL EDUCATIONAL POLICY 2020

Surekha Pandit
Librarian, Government College, Rau
Surekhapandit281@gmail.com

Abstract

Library is an integral part of education system and plays an important role in teaching, learning, research that ultimately support in the socio-economic development of the nation. Libraries are not only the storehouse of books; rather they work to preserve the literary, cultural and historical heritage of the country forfuture generation.

The National Education Policy 2020 (NEP-2020), emphasizing the role of the library from school education to higher education, and underlining the significance of the library in developing reading habits, lifelong learning, adult education as well as in education for disabled.The NEP-2020 focuses on strengthening the infrastructure and services of academic as well as public libraries by providing adequate resources that include books and digital resources.

The objective of the paper is to determine the role of libraries in perspective of NEP-2020 and to identify the challenges and opportunities for libraries.

Keywords: Education policy, Libraries, Library collection, Library services.